सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 270, नई दिल्ली । सोमवार, 09 दिसम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे।

03 मौजूदा हालात में मुबाहसा की नहीं, मुहासबा की जरूरत है: मुस्लिम मोर्चा
06 कार्य और अध्ययन- एक सिंहावलोकन
08 भुवनेश्वर में सीबीआई का छापा: 100 करोड़ रुपये की डील

अब निजी हाथों में होगी मेट्रो की कमान

डीएमआरसी ने दो एजेंसियों को किया फाइनल

संजय बाटला

दिल्ली मेट्रो की कमान अब निजी हाथों में होगी। डीएमआरसी ने पिछले वर्ष दिसंबर में यलो लाइन के साथ-साथ वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट-बल्लभगढ़) पर और इस वर्ष जनवरी में रेड लाइन (रिठाला-शहीद स्थल न्यू बस अड्डा गाजियाबाद) और ग्रीन लाइन (कीर्ति नगर-बाहादूरगढ़) पर भी मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग के आधार पर निजी एजेंसियों को सौंपने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी।

नई दिल्ली। येलो इन के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने अब वायलेट, रेड व व ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो का परिचालन निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके तहत डीएमआरसी ने दो निजी एजेंसियों को नियुक्त किया है, जो यलो लाइन के अलावा वायलेट लाइन, रेड लाइन व ग्रीन लाइन इन तीन कॉरिडोर पर भी मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी संभालेंगी।

डीएमआरसी ने क्यों लिया ये फैसला?

इन दोनों निजी एजेंसियों द्वारा नियुक्त चालक जल्द मेट्रो परिचालन की कमान संभाल लेंगे। इससे दिल्ली मेट्रो के चार कॉरिडोर व 158.68 किलोमीटर नेटवर्क पर मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों के हाथों में होगी।

मेट्रो परिचालन का खर्च कम करने के लिए डीएमआरसी ने करीब चार वर्ष पहले यलो लाइन (समयपुर बादली-मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम) की मेट्रो से स्थायी ट्रेन ऑपरेटरों को हटाकर आउटसोर्सिंग के आधार पर निजी एजेंसी की सेवाएं लेने की पहल की थी। तब से अभी तक सिर्फ यलो लाइन पर ही निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी मेट्रो का परिचालन करते हैं। इसके टेंडर की अवधि भी इस माह खत्म होने को है।

मेट्रो चलाने के लिए 600 कर्मचारियों की होगी तैनात

डीएमआरसी का कहना है कि यलो व वायलेट लाइन पर मेट्रो परिचालन के आउटसोर्सिंग के लिए जेएमडी कंसल्टेंट नामक एजेंसी को टेंडर आवंटित किया गया है, जो मेट्रो परिचालन के लिए 600 कर्मचारी तैनात करेगी। जिसमें चालक, ट्रेन अधीक्षक व प्रबंधक शामिल होंगे। इस एजेंसी द्वारा नियुक्त 52 कर्मचारियों का अभी डीएमआरसी के एकेडमी में प्रशिक्षण चल रहा है।

अभी 26 कर्मचारियों का चल रहा प्रशिक्षण

इस माह के अंत तक निजी एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी यलो व वायलेट लाइन की मेट्रो में तैनात हो जाएंगे। रेड व ग्रीन लाइन पर मेट्रो परिचालन के आउटसोर्सिंग के लिए न्यूविजन कमर्शियल और एस्कार्ट सर्विसेज नामक एक एजेंसी नियुक्त की गई है। यह एजेंसी रेड व ग्रीन लाइन पर मेट्रो परिचालन के लिए चालक सहित करीब 350 कर्मचारियों को नियुक्त करेगी। जिसमें से अभी 26 कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है।

अगले वर्ष फरवरी से इस एजेंसी द्वारा नियुक्त चालक रेड व ग्रीन लाइन पर चरणबद्ध तरीके से मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी संभाल लेंगे। लेकिन डीएमआरसी ट्रेनों के परिचालन की निगरानी जारी रखेगा। इसके अलावा वायलेट, रेड व ग्रीन लाइन की मेट्रो में वर्तमान समय में तैनात ट्रेन ऑपरेटरों से तकनीकी कार्य लिए जाएंगे।

मेट्रो में तकनीकी समस्याओं के समाधान, इमरजेंसी की स्थिति में बचाव कार्य व निजी कर्मचारियों की काउंसलिंग के कार्य में ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा वे फेज चार की मेट्रो में भी वे नियुक्त किए जाएंगे।

चारों कॉरिडोर की लंबाई (किलोमीटर में) व स्टेशनों की संख्या कॉरिडोर लंबाई

येलो लाइन	49.02	37
वायलेट लाइन	46.34	34
रेड लाइन	34.54	29
ग्रीन लाइन	28.78	24
कुल	158.68	124

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय:- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

गुरुग्रामवासियों की नए साल से बढ़ेंगी मुश्किलें, ऑटो चालकों पर लागू हो रहा नया नियम; सफर में आएंगी दिक्कतें

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम में डीजल ऑटो पर प्रतिबंध लगने जा रहा है। एक जनवरी से पूरे जिले में डीजल ऑटो चलाने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। डीजल ऑटो की जगह अब सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रतिबंध से लोगों को यात्रा में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

गुरुग्राम। साइबर सिटी सहित पूरे जिले में एक जनवरी से डीजल ऑटो चलाने पर पूरी तरह रोक लग जाएगी। इससे पहले 31 दिसंबर तक डीजल ऑटो जब्त करने का अभियान चलाया जाएगा।

इस बारे में उपायुक्त अजय कुमार ने शनिवार को अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी एसडीएम, क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के सचिव व पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि 31 दिसंबर के बाद सड़कों पर कहीं भी डीजल ऑटो नहीं दिखने चाहिए।

सर्दी की शुरुआत में ही लगा ग्रेप

पिछले कुछ सालों से पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। सर्दी की शुरुआत के साथ ही ग्रेप लागू करने की नौबत आ जाती है। प्रदूषण के पीछे एक कारण डीजल ऑटो भी हैं।

गुरुग्राम में अग्रवाल धर्मशाला चौक, अग्रसेन चौक, फव्वारा चौक, सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नजदीक, हीरो होंडा चौक, इफको चौक सहित कई चौराहों के नजदीक प्रदूषण का स्तर इतना अधिक रहता है कि कई बार सांस लेने में भी लोगों को परेशानी होती है।

डीजल ऑटो पर पहले भी हुआ था प्रतिबंध लगाने का प्रयास

आंखों में जलन की शिकायत बढ़ जाती है। इसे देखते हुए डीजल ऑटो को पूरी तरह बंद करने पर प्रशासन कई साल से विचार कर रहा है। दो साल पहले प्रशासन ने डीजल ऑटो पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में कमी की वजह से लोगों को दिक्कत आने पर प्रशासन ने कदम पीछे कर लिया था।

सड़कों पर आ चुके हैं हजारों CNG और इलेक्ट्रिक ऑटो

अब सड़कों पर हजारों की संख्या में सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक ऑटो आ चुके हैं। यही नहीं पिछले दो साल में सिटी बस सेवा भी काफी बेहतर हुई है। इससे उम्मीद है कि डीजल ऑटो बंद किए जाने से लोगों को परेशानी नहीं होगी।

वर्तमान में जिले में सभी प्रकार के ईंधन से चालित ऑटो की संख्या 38,400 है। इनमें से डीजल ऑटो की संख्या 1015 है। जिले में में एक जनवरी 2023 से डीजल ऑटो का पंजीकरण नही किया जा रहा है। कुछ महीनों के दौरान 80 से अधिक डीजल ऑटो जब्त किए जा चुके हैं।

31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश

एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 30 नवंबर 2022 को एनसीआर क्षेत्र में सड़कों से डीजल ऑटो हटाने के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित की थी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के लिए 31 दिसंबर 2024 की समय सीमा तय की गई थी। साथ लगते अन्य जिलों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित है।

एक जनवरी से कहीं भी डीजल ऑटो दिखाई नहीं देंगे। गुरुग्राम प्रदेश की आइकन सिटी है। इसे अंतरराष्ट्रीय शहरों के समकक्ष बनाने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के उपाय

किए जा रहे हैं। इन उपायों के अंतर्गत डीजल ऑटो को सड़कों से हटाना जरूरी है। शेयरिंग ऑटोरिक्शा में सवारियों की क्षमता का भी ध्यान रखा जाएगा। यदि कोई ऑटो बिना पंजीकृत नंबर के चल रहा है तो उसको तुरंत प्रभाव से जब्त किया जाएगा। - अजय कुमार, उपायुक्त, गुरुग्राम

ग्रेप-4 की पाबंदियां हटने के बाद फिर 'खराब' हुई दिल्ली की हवा, कई इलाकों का AQI 300 के पार

दिल्ली एनसीआर से ग्रेप-4 की पाबंदियां हटने के बाद एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी के कई इलाकों का एक्यूआई रविवार को 300 के पार पहुंच गया जो प्रदूषण की बहुत खराब श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में सुबह आठ बजे एक्यूआई 352 दर्ज किया गया। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

नई दिल्ली। दिसंबर महीने की शुरुआत में वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिलने के बाद दिल्ली-एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) फिर से बढ़ रहा है। प्रदूषण से कुछ राहत मिलने के बाद दिल्ली-एनसीआर से ग्रेप-4 की पाबंदियां हटा दी गई। इसके बाद से वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक, आज रविवार को दिल्ली के कई इलाकों का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया है। रविवार सुबह दिल्ली का औसत एक्यूआई 261 दर्ज किया गया, प्रदूषण की 'खराब' श्रेणी में आता है।

किस इलाके में कितना है AQI

स्थान	एक्यूआई	श्रेणी
आनंद विहार	352	बहुत खराब
जहांगीरपुरी	321	बहुत खराब
चांदनी चौक	332	बहुत खराब
अलीपुर 277	खराब	
आया नगर	229	खराब
द्वारका सेक्टर-8	268	खराब
नजफगढ़ 214	खराब	
इंदिरापुरम, गाजियाबाद	261	खराब
लोनी, गाजियाबाद	226	खराब
नोएडा सेक्टर-62	219	खराब

(ये आंकड़े सुबह आठ बजे सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं।)

वहीं, मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार, आज सुबह दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरे की एक पतली परत छाई रही और न्यूनतम तापमान गिरकर 8 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। नोएडाः चार दिन से रोजाना बढ़ रहा प्रदूषण, एक्यूआई 179 दर्ज, शनिवार को गौतमबुद्ध नगर का एक्यूआई चार दिनों में सबसे ज्यादा 179 रिकार्ड हुआ। सेक्टर-62 स्टेशन में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में 201 पहुंच गई जो शुक्रवार को 162 पर थी।

68 गांवों से होकर गुजरेगा यह लिंक एक्सप्रेसवे, 17 गांव गौतमबुद्ध नगर और तीन गांव न्यू नोएडा में हैं

खुशखबरी: नोएडा में बनेगा लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट से होगी गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी; लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा एयरपोर्ट को जोड़ने वाली लिंक एक्सप्रेसवे के संरेखण को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपीडा और यीडा के अधिकारियों के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी है। लिंक एक्सप्रेसवे को फिल्म सिटी के पास यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर सहमति बनी है। अंतिम निर्णय यूपीडा के सीईओ और यमुना प्राधिकरण के सीईओ की बैठक में होगा।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रमुख सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी के लिए लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइन्मेंट जल्द फाइनल होगा। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और यमुना प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारियों के बीच लिंक एक्सप्रेसवे के एलाइन्मेंट को लेकर दो दौर की वार्ता चुकी है।

बैठक में लगेगी लिंक एक्सप्रेसवे पर अंतिम मुहर

लिंक एक्सप्रेसवे को फिल्म सिटी के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने पर सहमति बनी है। इस पर अंतिम निर्णय यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह की बैठक में होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए इसे यमुना एक्सप्रेसवे के अतिरिक्त दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से लिंक एक्सप्रेसवे बनाकर जोड़ा जा रहा है।

यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया नोएडा एयरपोर्ट

लिंक एक्सप्रेसवे का काम मार्च तक पूरा होने की संभावना है। इसे यमुना एक्सप्रेसवे व नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए यूपीडा ने लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार किया था।

एयरपोर्ट तक लिंक एक्सप्रेसवे का एलाइन्मेंट जल्द

सर्वे के बाद तैयार एलाइन्मेंट के तहत इसे एयरपोर्ट के नजदीक यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना थी, लेकिन यह क्षेत्र एमआरओ के लिए आरक्षित होने के कारण

प्राधिकरण ने यूपीडा को एलाइन्मेंट में बदलाव के लिए पत्र लिखने के साथ विकल्प सुझाए थे। यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि लिंक एक्सप्रेसवे का नया एलाइन्मेंट किया गया है।

130 मीटर रोड से भी जुड़ेगा लिंक एक्सप्रेसवे

यीपीडा सीईओ व यीडा सीईओ की बैठक में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नए एलाइन्मेंट के तहत सेक्टर 21 में फिल्म सिटी के नजदीक 130 मीटर रोड से जोड़ा जाएगा। इसके जरिये लिंक एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में इसकी लंबाई तकरीबन 20 किमी होगी।

लिंक एक्सप्रेसवे से किसे मिलेगा फायदा?

लिंक एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे के 44 किमी प्वाइंट से शुरू होगा। यह बुलंदशहर और गौतमबुद्ध नगर के 68 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें 17 गांव गौतमबुद्ध नगर और तीन गांव न्यू नोएडा में हैं। लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से नोएडा एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक हो जाएगी।

बीमा सखी योजना: ग्रामीण महिलाओं को बनायेगी सशक्त

भारत के प्रधानमंत्री 9 दिसम्बर 2024 को पानीपत से महिलाओं के लिए 'बीमा सखी' योजना शुरू करेंगे। उल्लेखनीय है कि उन्होंने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान भी शुरू किया था। बीमा सखी योजना का उद्देश्य बीमा के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देता है और पूरे भारत में आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाता है। हरियाणा का पानीपत शहर ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण है। यह अपनी लड़ाइयों के लिए जाना जाता है और अब भारत में महिला सशक्तिकरण पहलों का केंद्र बिंदु है।

-प्रियंका सौरभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 दिसम्बर को पानीपत का दौरा करेंगे और ₹बीमा सखी योजना₹ शुरू करेंगे, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। 9 दिसम्बर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के पानीपत में 'बीमा सखी योजना' की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत, महिलाएँ जीवन बीमा निगम की एजेंट बनेंगी, जिससे वे बीमा बेच सकेंगी और आय अर्जित कर सकेंगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। ₹बीमा सखी योजना₹ महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा पर केंद्रित है, जो महिलाओं के लिए बीमा कवरेज को बढ़ावा देती है। यह योजना महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना है।

यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। महिलाओं को बीमा उत्पादों तक पहुँच प्राप्त होगी, जो कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। इस सहायता का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। इस लॉन्च से महिलाओं के सशक्त होने की उम्मीद है। यह लैंगिक समानता के बारे में एक मज़बूत संदेश भेजेगा। यह पहल महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य महिलाओं को अपने भविष्य की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना है। 'बीमा सखी योजना' पूरे भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत चुनी गई महिलाएँ एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी और अपने समुदायों में बीमा सेवाएँ प्रदान करेंगी। इससे न केवल महिलाओं के लिए रोजगार पैदा होगा बल्कि वित्तीय साक्षरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से गहरा नाता है, अक्सर वे इसे महत्त्वपूर्ण पहलों के लिए लॉन्चिंग ग्राउंड के रूप में चुनते हैं। 2015 में पानीपत से 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' आंदोलन की शुरुआत सहित मोदी के अभियानों के साथ राज्य का इतिहास महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी निरंतर प्रतिबद्धता के लिए एक मिसाल क़ायम करता है। महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान देने के लिए जाना जाने वाला हरियाणा एक बार फिर सामाजिक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने की राज्य की विरासत को और मज़बूत करेगी। 'बीमा सखी योजना' राज्य की सफल महिला-केंद्रित नीतियों के पोर्टफोलियो में शामिल होगी और समावेशी विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाएगी। 'नारी शक्ति' पर सरकार के ज़ोर को लोकसभा में पारित 'नारी शक्ति वंदन विधेयक' जैसे प्रयासों के माध्यम से मज़बूत किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया।

बीमा सखी योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रगतिशील पहल है। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना लैंगिक समानता और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप है। यह वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह पहल वित्तीय सेवाओं में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करते हुए स्थायी आजीविका बनाने का प्रयास करती है। इस योजना से महिलाओं को वित्तीय मुख्यधारा में एकीकृत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। लैंगिक समानता: यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बीमा सखी जैसी पहलों के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। एक स्थिर आय और करियर पथ प्रदान करके, कार्यक्रम कमजोर समुदायों की महिलाओं का उत्थान करना चाहता है।

पात्र महिलाओं को योजना के बारे में सूचित करने के लिए प्रभावी संचार रणनीतियाँ आवश्यक हैं। योजना की सफलता के लिए वेतन और कमीशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है। बीमा क्षेत्र में अपनी भूमिका को बनाए रखने और विस्तारित करने के लिए महिला एजेंटों के लिए एक मज़बूत सहायता प्रणाली का निर्माण करना। आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए। न्यूनतम योग्यता 10वीं या 12वीं कक्षा की होनी चाहिए। आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, शैक्षिक प्रमाण पत्र शामिल हैं और महिलाओं को ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों की निवासी होना चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को बीमा सखी के रूप में तैयार करने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किए गए विशेष प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। प्रशिक्षण के सफल समापन पर प्रमाणन प्रदान किया जाता है। एक निश्चित मासिक वेतन: पहले वर्ष में ₹7,000, दूसरे में ₹6,000 और तीसरे वर्ष में ₹5,000 और बेची गई बीमा पॉलिसियों पर कमीशन के माध्यम से अतिरिक्त आय मिलेगी।

आयोगों और नीति-सम्बंधी अपडेट की निगरानी के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। कौशल और ज्ञान को उन्नत करने के लिए नियमित कार्यशालाएँ। देश भर में 35,000 महिलाओं को शामिल करने की प्रारंभिक योजना। हरियाणा का पानीपत, महिला सशक्तिकरण पर अपने ऐतिहासिक ज़ोर के कारण इस योजना का लॉन्चपैड है। आधिकारिक या नामित सरकारी पोर्टल पर जाएँ। व्यक्तिगत विवरण और वैध संपर्क जानकारी का उपयोग करके एक खाता बनाएँ। सटीक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। आईडी प्रूफ, शैक्षिक प्रमाण पत्र और बैंक विवरण जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। आवेदनों की समीक्षा की जाती है। स्वीकृत होने के बाद, उम्मीदवारों को एक व्यक्तिगत डैशबोर्ड तक पहुँच प्राप्त होती है। 'बीमा सखी योजना' 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'नमो दीदी' कार्यक्रमों की सफलता के बाद, महिला-केंद्रित योजनाओं को शुरू करने के पीएम मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को जारी रखती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका निरंतर प्रयास समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और विधायी परिवर्तनों में स्पष्ट है।

बीमा सखी योजना वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। ग्रामीण महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाकर, यह योजना न केवल उन्हें आजीविका के अवसर प्रदान करती है बल्कि उन्हें औपचारिक वित्तीय प्रणाली में भी एकीकृत करती है। कार्यक्रम की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन और हितधारकों से निरंतर समर्थन पर निर्भर करती है।

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, हिसार (हरियाणा)-127045

बैन ड्रग्स के लिए युवाओं में बढ़ती तलब

हाल ही में, एक जांच से पता चला है कि नशीली दवाओं की लत की महामारी, जो ज्यादातर युवा पुरुषों को प्रभावित कर रही है, पूरे भारत में फैल रही है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग भारत में एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य मुद्दा है। भारत की विविध आबादी, बड़ी युवा जनसांख्यिकी और आर्थिक असमानताएँ देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की जटिल प्रकृति में योगदान करती हैं। सांस्कृतिक मूल्यों को बदलना, आर्थिक तनाव में वृद्धि और सहायक सम्बंधों में कमी से पदार्थ का उपयोग शुरू हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 75 वर्ष की आयु के 16 करोड़ लोग (14.6%) शराब के वर्तमान उपयोगकर्ता हैं और उनमें से 5.2% शराब पर निर्भर हैं। लगभग 3.1 करोड़ व्यक्ति (2.8%) भांग उपयोगकर्ता हैं और 72 लाख (0.66%) लोग भांग की समस्या से पीड़ित हैं 7% बच्चे और किशोर इनहेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वयस्कों में यह दर 0.58% है। लगभग 18 लाख बच्चों को इनहेलेंट के इस्तेमाल के लिए मदद की ज़रूरत है। अनुमान है कि लगभग 8.5 लाख लोग इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स ले रहे हैं। भारत में ड्रग्स की सबसे चिंताजनक श्रेणी ओपिओइड है, भारत में ओपिओइड के इस्तेमाल का प्रचलन वैश्विक औसत (0.7% बनाम 2.1%) से तीन गुना ज़्यादा है। सभी ड्रग श्रेणियों में, ओपिओइड समूह (विशेष रूप से हेरोइन) की ड्रग्स बीमारी, मृत्यु और विकलांगता की सबसे ज़्यादा दरों से जुड़ी हैं।

-डॉ सत्यवान सौरभ

ड्रग के दुरुपयोग से कई तरह की शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जिनमें लीवर की बीमारी (शराब से), संक्रामक रोग (इंजेक्शन ड्रग के इस्तेमाल में सुइयों को साझा करने के कारण) और ओवरडोज़ से होने वाली मौतें शामिल हैं। साथ ही, मादक द्रव्यों के सेवन का मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे अवसाद और चिंता से गहरा सम्बंध है। यह मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकता है या नए लोगों के विकास को जन्म दे सकता है। ड्रग के दुरुपयोग से परिवार टूट सकते हैं, संघर्ष बढ़ सकते हैं और परिवारों के भीतर भावनात्मक आघात हो सकता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से प्रभावित परिवारों में बच्चों को उपेक्षा, दुर्व्यवहार और शिक्षा में बाधा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी समग्र भलाई प्रभावित होती है। नशीली दवाओं की लत से जूझ रहे व्यक्तियों को अक्सर सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है, जो उनके ठीक होने और समाज में फिर से शामिल होने में बाधा बन सकता है। परिवार के किसी सदस्य की लत को सहने की लागत और उससे जुड़े चिकित्सा व्यय के कारण परिवारों को अक्सर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता 18-35 वर्ष की उत्पादक आयु वर्ग में होते हैं, नशीली दवाओं की लत के कारण कार्यस्थल पर अनुपस्थिति और उत्पादकता में कमी आ सकती है। हिंसा और अपराध में वृद्धि नशीली दवाओं के दुरुपयोग का प्रत्यक्ष प्रभाव है। नशे के आदी लोग अपनी दवाओं के भुगतान के लिए अपराध का सहारा लेते हैं। नशीली दवाएँ संकोच को दूर करती हैं और निर्णय लेने की क्षमता को कम करती हैं, जिससे व्यक्ति अपराध करने के लिए प्रेरित होता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के साथ छेड़छाड़, समूह संघर्ष, हमला और आवेगपूर्ण हत्याओं की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

आम आबादी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखिमों और इसके परिणामों के बारे में सीमित जागरूकता है। इसके अलावा, स्कूलों और समुदायों में लोगों, विशेष रूप से युवा व्यक्तियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में सूचित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम अपर्याप्त हैं। मादक द्रव्यों के सेवन के विकार वाले व्यक्तियों को कलंकित करने से वे सहायता और समर्थन प्राप्त करने से हतोत्साहित हो सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और समाज में बड़े पैमाने पर भेदभाव उपचार और पुनर्वास सेवाओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं की लत के उपचार सुविधाओं और योग्य स्वास्थ्य पेशेवरों की भारी कमी है। भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रचलन और पैटर्न पर सीमित शोध है, जो साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण और कार्यक्रम विकास में बाधा डालता है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की छिपी और कलंकित प्रकृति के कारण सटीक डेटा एकत्र करने में भी चुनौतियाँ हैं। प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों के करीब भारत की भौगोलिक स्थिति इन दवाओं की आसान उपलब्धता की ओर ले जाती है। इसके अलावा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार के लिए 'डार्क नेट' और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। भारत में नए साइकोएक्टिव पदार्थों की खपत बढ़ रही है और ये पदार्थ अक्सर मौजूदा दवा नियंत्रण नियमों के दायरे से बाहर हो जाते हैं, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें प्रभावी ढंग से मॉनिटर और विनियमित करना चुनौती बन जाता है।

व्यापक विधायी नीति तीन केंद्रीय अधिनियमों में निहित है, अर्थात औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम। यह भारत में नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन के लिए नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में देश भर में नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन प्रयासों के समन्वय के लिए की गई थी। नशीली दवाओं के कानून प्रवर्तन में हितधारकों की बहुलता ने वास्तविक समय के आधार पर विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को आवश्यक बना दिया है। गृह मंत्रालय ने जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक देश भर के हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाने और नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए चार-स्तरीय समन्वय तंत्र का गठन किया है। शीर्ष एनसीओआरडी, कार्यकारी एनसीओआरडी, राज्य एनसीओआरडी और ज़िला कॉर्ड तंत्र के चार स्तंभ हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) नशे की लत के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (आईआरसीए) के रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ये केंद्र मादक द्रव्यों के सेवन के विकारों वाले व्यक्तियों को व्यापक पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करते हैं। एमओएसजेई ने 2018-2025 के लिए एनएपीडीडीआर शुरू किया। योजना का उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रतिकूल परिणामों को कम करना है।

सरकार को सीमा शुल्क, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य पुलिस बलों सहित नशीली दवाओं के नियंत्रण में शामिल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को मज़बूत करने के लिए उपाय करने चाहिए। इसमें उन्हें बेहतर प्रशिक्षण, तकनीक और संसाधन प्रदान करना शामिल हो सकता है। गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी में योगदान कर सकते हैं। इसलिए, सरकार ग़रीबी कम करने के उपायों, रोजगार सर्जन योजनाओं और शिक्षा तक पहुँच बढ़ाकर इन मुद्दों को सम्बोधित कर सकती है। नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए समुदाय-आधारित रोकथाम कार्यक्रम, शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें रोकथाम, शिक्षा, उपचार, नुक़सान में कमी, नीति सुधार और समुदाय की भागीदारी में वृद्धि शामिल है। भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदाय के बीच सहयोग आवश्यक है।

ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए हॉट चॉकलेट की इन रेसिपीज को घर में बनाएं, नोट करें विधि

दिव्यांशी भदौरिया

सर्दियों में ठंडी हवाएं काफी जोर से चलती है। ठंड के मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए आप हॉट चॉकलेट ड्रिंक जरुर पिएं। यह मजेदार बेवरेज के सेवन से आपको सर्दियों में गर्माहट जरुर मिलेगी। आइए आपको इनकी रेसिपीज बताते हैं।

ठंड के मौसम में कंबल में सोते रहना सभी को अच्छा लगता है इसके साथ ही हॉट चॉकलेट का मग मिल जाए तो और भी आनंद आ जाता है। हॉट चॉकलेट गाढ़ा और मीठा डेजर्ट बेवरेज है जो गर्माहट प्रदान करने के साथ-साथ चॉकलेटी स्वाद से मन को खुश कर सकते हैं। आप हॉट चॉकलेट के कई फ्लेवर ट्राई कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसी रेसिपीज बताएंगे जिनका आप आसानी से बना सकते हैं और स्वाद भी लाजवाब हो।

क्लासिक क्रीमी हॉट चॉकलेट

सामग्री-

-2 कप मिल्क

-2 चम्मच बिना चीनी वाला कोको पाउडर

-2 चम्मच चीनी

-1/4 चम्मच वनिला एक्सट्रैक्ट

-टॉपिंग के लिए व्हीप्ड क्रीम या मार्शमैलो

इसे बनाने का तरीका

- सबसे पहले आप सॉस पैन में मीडियम आंच पर दूध गर्म करें। ध्यान रहे कि दूध को उबालना नहीं है।

- इसमें कोको पाउडर और चीनी डालें। इसके साथ ही चीजों को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं।

- सभी चीजें अच्छे से घुल जानी चाहिए।

- वनिला एक्सट्रैक्ट डालकर मिक्स करें। दूध को अच्छे से पकने दें।

- फिर आप मग में गर्मागर्म डेजर्ट बेवरेज डालें और ऊपर से व्हिप्ड क्रीम या मार्शमैलो डालकर सर्व करें।

पेपरमिंट हॉट चॉकलेट

सामग्री

-2 कप दूध

-2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर

-2 बड़ा चम्मच चीनी

-1/2 छोटा चम्मच पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट

-गार्निश के लिए क्रश की हुई कैंडी केन

बनाने का तरीका

- दूध को गर्म कर लें, ध्यान रहे उबालना नहीं है।

- दूध पकने पर उसमें कोको पाउडर और चीनी मिला लें।

- फिर आप पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट डालें। ध्यान रखें कि इसे पहले कम मात्रा में डालें। नहीं तो आपकी हॉट चॉकलेट कड़वी हो जाएगी।

मैक्सिकन हॉट चॉकलेट

सामग्री

-2 कप दूध

-2 बड़ा चम्मच कोको पाउडर

-2 बड़ा चम्मच चीनी

-1/2 छोटा चम्मच दालचीनी

-एक चुटकी लाल मिर्च

बनाने का तरीका

- जैसे ऊपर बताया कि दूध को गर्म कर लें।

- अब इसमें कोको पाउडर, दालचीनी और लाल मिर्च डालकर फेंटें।

- इसमें एकदम स्मूथ होने तक मिक्स करें। सर्विंग मग में डालें और दालचीनी के टुकड़े डालें।

व्हाइट चॉकलेट रास्पबेरी हॉट चॉकलेट

सामग्री

-2 कप दूध

-1/2 कप व्हाइट चॉकलेट चिप्स

-2 बड़े चम्मच रास्पबेरी सिरप

-सजावट के लिए ताजी रास्पबेरी

बनाने का तरीका

- सबसे पहले आप दूध गर्म कर लें। इसके बाद इसमें व्हाइट चॉकलेट चिप्स को धीमी आंच पर पिघलाएं।

- जब व्हाइट चॉकलेट पिघल जाएं, तो इसमें रास्पबेरी सिरप मिलाएं।

- इसे मग में डालकर ऊपर से फ्रेश रास्पबेरी से सजाकर इसका मजा लें।

सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए बैंगन के सूप का करें सेवन

अनन्या मिश्रा

सर्दियों के मौसम में सिरदर्द-बलगम जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए बैंगन के सूप का सेवन करना चाहिए। बता दें कि बैंगन का सूप स्वास्थ्य के लिए बेशकीमती वरदान साबित हो सकता है।

सर्दियों में शरीर को ठंड से बचाकर रखना होता है। लेकिन कई बार ठंडी हवा लग जाने की वजह से कुछ आम बीमारियां हो जाती है। वहीं आम दिखने वाली बीमारियां काफी परेशान भी करती हैं। लेकिन शायद है कोई हो जो इन समस्याओं से बच पाता होगा। जिन लोगों को कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलना पड़ता है, उन्हें अक्सर सिरदर्द और बलगम जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

क्योंकि सर्दियों के मौसम में सिरदर्द-बलगम जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए बैंगन के सूप का सेवन करना चाहिए। बता दें कि बैंगन का सूप स्वास्थ्य के लिए बेशकीमती वरदान साबित हो सकता है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बैंगन का सूप बनाने की विधि और इसको पीने के सही तरीके के बारे में बताने जा रहे हैं।

इसे भी पढ़ें: Health Tips: सर्दियों में इन तरीकों से डाइट में शामिल करें खीरा, गैस और अपच जैसी समस्या से मिलेगी राहत

बैंगन सूप की सामग्री

बैंगन

अरहर दाल

कुलथी दाल

मूंग दाल

सेंधा नमक

पिप्पली और सौंठ

ऐसे बनाएं सूप

बैंगन का सूप बनाने के लिए मसालों को छोड़कर सारी चीजों को धो लें। अब बैंगन को काटकर दालों के साथ अच्छे से पानी में उबाल लें। इसके बाद उबले हुए मिक्सचर को छानकर पतला सूप तैयार कर लें। अब आप इसमें पिप्पली-सोंठ और सेंधा नमक जैसे मसाले मिला लें। इस तरह से बैंगन का सूप बनकर तैयार हो जाएगा।

सूप पीने का समय

बता दें कि सर्दियों में बैंगन का सूप पीने से काफी आराम मिलेगा। इसका सेवन खाने से थोड़ा पहले या हल्के भोजन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को बैंगन से एलर्जी है, उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए।

बैंगन का सूप पीने का फायदा

नाक की रुकावट खुलेगी

गंध की क्षमता ठीक रहेगी

बलगम कम होगा

सिरदर्द से राहत मिलेगी

पीरियड्स में कद्दू के बीज खाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, मिलते हैं गजब के फायदे

दिव्यांशी भदौरिया

सेहत के लिए कद्दू के बीज खाना बहुत ही लाभकारी सिद्द होता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं और हेल्दी फैट्स होते हैं जो हेल्थ के साथ ही पीरियड्स में कद्दू के बीज खाने से कई फायदे मिलते हैं। आइए आपको बताते हैं इसके फायदे ।विटामिन और फ़ूड सप्लीमेंट खरीदें

वैसे तो कद्दू के बीज सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें कई पोषक तत्व होते हैं। जैसे कि- फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पर्याप्त होती है। इतना ही नहीं, जिंक, आयरन, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए मौजूद होता है, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। सेहत के लिए काफी बढ़िया रहता ही अगर आप इसका सेवन पीरियड्स के दौरान भी करते हैं, तो भी काफी फायदेमंद होता है। पीरियड्स से जुड़ी कई समस्याओं में कद्दू के बीज खाना फायदेमंद माना गया है। तो चलिए आपको इसके फायदे जरुर बताते हैं।

पीरियड्स के समय कद्दू के बीज खाने से कई फायदे मिलते हैं

क्रैम्प्स में राहत होती

आमतौर पीरियड्स के दौरान क्रैम्प्स काफी होते हैं। अगर आप इस दौरान कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं, तो आपको काफी आराम मिल सकता है। क्योंकि, इसमें ग्नीशियम होता है जो यूट्रिन की मसल्स को रिलैक्स करता है।

ब्लड फ्लो मेंटेन करता

पीरियड्स के समय ब्लीडिंग काफी तेज होती है, जिससे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है। कद्दू के बीजों में आयरन होता है, जो खून की कमी को भी दूर करते है। क्योंकि कद्दू के बीजों में पर्याप्त मात्रा में आयरन पाया जाता है ।विटामिन और फ़ूड सप्लीमेंट खरीदें

मूड और नींद बेहतर होती है

आम बात है कि पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स जरुर होता है। अगर आप ऐसे में कद्दू के बीज खाने से मूड और स्लीप साइकिल बेहतर होती है। क्योंकि इसमें सेरोटोनिन होता है, जो मूड, नींद और तनाव के लेवल को मैनेज करता है।

ब्लोटिंग दूर होती है

कद्दू के बीजों के सेवन करने से ब्लोटिंग की समस्या दूर हो जाती है। पीरियड्स में यह समस्या काफी देखने को मिलती है। इससे मसल्स में खिंचाव कम होता है और दर्द में भी राहत मिलती है।

आयरन का स्तर बढ़ता है

पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग होने से कई लड़कियों में आयरन का स्तर काफी कम हो जाता है। ऐसे में आप कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं, तो आपका आयरन का स्तर काफी बढ़ जाएगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख के सुझाव सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन सुझावों और जानकारी को किसी डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल की सलाह के तौर पर न लें। किसी भी बीमारी के लक्षणों की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

'आप' को विधायक का टिकट काटना पड़ा महंगा, बागी हो गए पदाधिकारी; केजरीवाल को भेजा इस्तीफा

सुषमा रानी

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय का टिकट कटने के बाद तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मजबूत कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। अब तक 67 पदाधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल को अपने इस्तीफे भेजे हैं। इसके अलावा यमुनापार की दो विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों के चयन का विरोध हो रहा है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के लिए इस बार चुनौतियां बढ़ रही हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय का टिकट कटने पर तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के कई मजबूत कार्यकर्ताओं ने पद से इस्तीफा दिया। इनमें वार्ड, मंडल अध्यक्षों सहित विधानसभा और जिला स्तर के पदाधिकारी तक शामिल हैं।

ताजा जानकारी के मुताबिक, अब तक 67 पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को अपने इस्तीफे भेजे हैं। इस इस्तीफे में पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा से आए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू के लिए काम नहीं करेंगे। वहीं, यमुनापार की दो विधानसभा सीटों पर भी प्रत्याशियों के चयन का विरोध हो रहा है। ये सीटें घोंडा और रोहतास नगर हैं।

दिलीप पांडेय ने किया चुनाव नहीं लड़ने का एलान

बता दें कि दिलीप पांडेय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिमारपुर से वर्तमान में विधायक हैं। वह इस बार चुनाव नहीं लड़ने का एलान कर चुके हैं। इसके बाद से माना जा रहा है कि तिमारपुर विधानसभा सीट पर पार्टी सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू पर दांव लगा सकती है। बिट्टू तिमारपुर से कांग्रेस की टिकट से दो बार विधायक रहे चुके हैं।

दिलीप पांडे के फैसले से क्या बढ़ेंगी AAP की मुश्किलें? केजरीवाल के लिए कही अहम बात

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2025 में विधानसभा होने प्रस्तावित हैं। चुनाव की तारीखों की सुगबुगाहट से पहले ही आम आदमी पार्टी पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है।

भाजपा के चुनावी नारे से केजरीवाल परेशान- सचदेवा

इससे पहले, शनिवार को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, ₹अपने खोते जनाधार, सरकार एवं विधायकों के प्रति जनता के आक्रोश से अरविंद केजरीवाल हताश हो गए हैं। यही कारण है कि वह भाजपा के चुनावी नारा को लेकर अनर्गल बयानबाज़ी कर रहे हैं। भाजपा का चुनावी नारा ₹अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे₹ जारी होते ही जनता की जुबान पर चढ़ गया है। यह परिवर्तन का नारा है। इससे केजरीवाल के झूठे प्रचार पर कुठारघात हुआ है।

उन्होंने आगे कहा, ₹दिल्लीवासी आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। वह जानते हैं कि भाजपा की सरकार बनने पर दिल्ली में निशुल्क बिजली- पानी और महिलाओं की बस यात्रा को बेहतर तरीके से लागू करेगी। लोगों की समस्याएं दूर होगी, लेकिन भ्रष्टचार के आरोपों से घिरे आप नेताओं की परेशानी बढ़ जाएगी।

मौजूदा हालात में मुबाहसा की नहीं, मुहासबा की जरूरत है: मुस्लिम मोर्चा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा द्वारा आयोजित, बाबरी मस्जिद की शहादत के तीन दशकों के बाद भी, देश ने काला दिवस, शोक दिवस के प्रचलित रीति-रिवाजों से अलग मुहासबा दिवस (हिसाब-किताब का दिन) का आयोजन किया।इस अवसर पर मोर्चा के सभी पदाधिकारियों और समर्थकों को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने कहा कि देश में शरारत, उकसावे और सांप्रदायिकता के एजेंडे को आगे बढ़ाना मुट्ठी भर लोगों का काम है। अधिकांश आबादी शांति और प्रेम में विश्वास करती है। हमें शांतिपूर्ण लोगों को साथ लेकर घृणित समूह को हराने की जरूरत है, हमें अपने जीवन में इस्लाम के इस सिद्धांत को अपने सामने रखते हुए काम करने की जरूरत है। जिसे मिसाके मदीना के नाम से जाना जाता है।

हाफिज गुलाम सरवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश की मनोदशा को समझे बिना कोई भी नीति बनाना अल्पसंख्यकों के लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा देश के अल्पसंख्यकों से अपील करता है कि वे नकारात्मक सोच और नकारात्मक बातें छोड़ दें और सकारात्मक तरीके से इस्लाम के वास्तविक सिद्धांत के साथ देश के भाइयों और बहनों के साथ शांति और विश्वास की बहाली के लिए काम करें।

महासचिव शब्बीर अहमद मंसूरी ने भी देश में संभावनाओं पर विस्तार से बात की, अब्दुल जब्बार पहलवान ने अध्यक्षता की। जबकि अन्य अधिकारियों में मुहम्मद अकरम सागर, रईस अहमद सैफी, मुहम्मद इरशाद, यूसुफ मंसूरी, मुहम्मद आजम, तौकीर अंसारी, अशरफ अंसारी आदि शामिल थे। उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए।समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

सिख वोटों पर अरविंद केजरीवाल की नजर, तीन दिन में दो सिख नेता आम आदमी पार्टी में शामिल

इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) सिख वोटों पर नजर गड़ाए हुए है। पिछले तीन दिनों में आम आदमी पार्टी ने दो सिख नेताओं जितेंद्र सिंह शंटी और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल किया है। इस समय दिल्ली में आप के सिर्फ दो सिख विधायक हैं। पार्टी विधानसभा चुनाव में सिखों की हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति में जुट गई है।

नई दिल्ली। पंजाब के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिखों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के प्रयास में है। इसी क्रम में पिछले तीन दिनों में आप ने दो सिख नेताओं जितेंद्र सिंह शंटी और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल कराया है।

इस समय दिल्ली में आप के सिर्फ दो सिख विधायक हैं। जिसमें से तिलक नगर से जनरैल सिंह व चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी शामिल हैं। जबकि 2015 में आप में चार सिख विधायक थे। लगातार कम हो रहे सिखों के प्रतिनिधित्व को लेकर अब आप गंभीर है और विधानसभा चुनाव में इस समाज की हिस्सेदारी बढ़ाकर उन्हें और बेहतर तरीके से अपनी ओर ले आने की रणनीति में जुट गई है।

अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को सिख नेता जितेंद्र सिंह शंटी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। फोटो- जागरण आर्काइव

दिल्ली में कितनी है सिख वोटरों की संख्या?

दिल्ली में सिख मतदाताओं की बात करें तो दिल्ली में करीब 10 लाख सिख मतदाता हैं। राजौरी गार्डन, तिलकनगर, कालकाजी, हरि नगर, कालकाजी व हरि नगर सीट पर सिखों की संख्या ठीक-ठाक है। मगर आमतौर पर हर सीट पर सिख मतदाता हैं। दिल्ली में सिख विधायक भी कभी ठीक-ठाक संख्या में रहे हैं।

AAP को विधायक का टिकट काटना पड़ा महंगा, बागी हो गए पदाधिकारी; केजरीवाल को भेजा इस्तीफा

2013 में जीते थे नौ सिख विधायक

सभी दलों के सिख विधायकों की बात करें तो 2013 में दिल्ली विधानसभा में नौ सिख विधायक चुन कर गए थे। इनमें आप के तीन, भाजपा के चार और दो कांग्रेस के थे। यानी आप से अधिक भाजपा के पास सिख विधायक थे।

इनमें आप के जंगपुरा से मनिंदर सिंह धीर, तिलक नगर से जरनैल सिंह व हरि नगर से जगदीप सिंह, भाजपा के राजेंद्र नगर से आरपी सिंह, शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा व कालकाजी से हरमीत सिंह कालका तथा कांग्रेस के गांधी नगर से अरविंद सिंह लवली व चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी का नाम शामिल है। मगर यह सरकार 49 दिन ही चल सकी थी।

2015 के चुनाव कितने सिख प्रत्याशी जीते?

2015 में जब फिर से आप की सरकार बनी तो सिख विधायक चार ही रह गए, ये भी आप के ही थे। इसमें तिलक नगर से जरनैल सिंह, हरि नगर से जगदीप सिंह व कालकाजी से अवतार सिंह जीते थे। इसके अलावा राजौरी गार्डन से भी जरनैल सिंह जीते थे, मगर 2017 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पंजाब जाकर चुनाव लड़े थे। इस सीट पर जब उप चुनाव हुए तो भाजपा के सिरसा ने फिर जीत हासिल की थी।

AAP ने मंत्रिमंडल किसी सिख चेहरे को नहीं दी जगह

कुल मिलाकर पंजाब में सरकार बना लेने के बाद दिल्ली में आप के लिए पहला चुनाव है। ऐसा कहा जा रहा है कि आप की फिर से सरकार बनती है तो इस बार मंत्रिमंडल में किसी सिख चेहरे को भी आप जगह दे सकती है। आप ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार के दो कार्यकाल में अभी तक किसी सिख को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। जबकि भाजपा और कांग्रेस दोनों की सरकारों में मंत्रिमंडल में सिखों का प्रतिनिधित्व रहा है।

नॉट फाउंड सूटेबल (NFS) के समय ऑब्जर्वर क्यों नहीं उठाते सवाल, अभ्यर्थी है पदों को भरा जाए

सुषमा रानी

दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विभागों व कॉलेजों में शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि विभिन्न विभागों / कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्तियों व पदोन्नति की प्रक्रिया पिछले दो साल से चल रही है। अभी तक लगभग 4800 पदों को भरा जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों व संबद्ध कॉलेजों में अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) व ओबीसी के अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्तियों में नॉट फाउंड सूटेबल (एनएफएस) किया जा रहा है। नॉट फाउंड सूटेबल किए जाने को लेकर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों में गहरा रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही क्यों नॉट फाउंड सूटेबल कर रहा है? वाणिज्य विभाग, शिक्षा विभाग, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, (एफएमएस) राजनीति विज्ञान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल के बंगाली विभाग के अलावा कॉलेज स्तर पर भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को एनएफएस किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। अभी हाल ही में हिन्दी विभाग में हुई एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर के पदों पर नियुक्तियों में ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल (एनएफएस) कर दिया गया जबकि अनरिजर्व पदों पर नियुक्ति कर ली गई। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस जल्द ही संसदीय समिति, नेशनल एससी,एसटी कमीशन, नेशनल ओबीसी कमीशन व सांसदों से मिलकर नॉट फाउंड सूटेबल संबंधी ज्ञापन देगा और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के विषय में बताएगा कि इन्हें ही नॉट फाउंड सूटेबल किया जाता है?

फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि डीयू के हिन्दी विभाग में हुई नियुक्तियों में ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया है जबकि अनरिजर्व पदों पर सभी नियुक्ति कर ली गई। यहाँ 1 एसोसिएट प्रोफेसर व 1 प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति की जानी थीं। बता दें कि पिछले दो साल से विभागों व कॉलेजों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व सहायक प्रोफेसर के 4800 पदों पर नियुक्तियां हुई है इनमें सबसे ज्यादा एससी/एसटी, ओबीसी श्रेणी के लगभग 200 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया है। जबकि साक्षात्कार देने आए अभ्यर्थियों में बेहतर कैंडिडेट उपलब्ध थे। उन्होंने बताया है कि इससे पहले भी डीयू के विभिन्न विभागों जैसे --- फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टरडीज (एफएमएस), राजनीति विज्ञान विभाग, शिक्षा विभाग (सीआईई) डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल के बंगाली विभाग व वाणिज्य विभागों में एससी /एसटी ओबीसी व ईडब्ल्यूएस कोटे के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि बहुत से विभाग एससी /एसटी, ओबीसी कोटे के अभ्यर्थियों की मेरिट वेटिंग लिस्ट भी नहीं बनाते। कुछ शिक्षकों के छोड़कर जाने के बाद उस मेरिट लिस्ट से पदों को भर लिया जाता है लेकिन ऐसा नहीं हो रहा?

डॉ. सुमन ने बताया है कि डीयू के विभिन्न विभागों जैसे -- फैकेल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टरडीज (एफएमएस) में सहायक प्रोफेसर के 29 पद विज्ञापित किए गए जिसमें 6 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। इनमें ओबीसी--04, एससी --01, एसटी --01 है। इसी तरह से पिछले दिनों राजनीति विज्ञान विभाग में भी ओबीसी --02 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया। वाणिज्य विभाग में भी ईडब्ल्यूएस कोटे के --02 उम्मीदवारों को भी नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। इसी विभाग में पिछले दिनों प्रोफेसर पद पर हुए साक्षात्कार में एससी -01 अभ्यर्थी को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। उन्होंने बताया है कि शिक्षा विभाग (सीआईई) में 5 पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। इसमें एससी --1 प्रोफेसर, एसटी --1 एसोसिएट प्रोफेसर, ओबीसी --1 एसोसिएट प्रोफेसर व ओबीसी --2 प्रोफेसर को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया। इसी तरह डिपार्टमेंट ऑफ एमआईएल, बंगाली विभाग में एससी--1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। उन्होंने बताया है कि स्थाई नियुक्ति के समय ऑब्जर्वर कुछ नहीं बोलते जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के पदों की देखरेख वहीं करते हैं।

उन्होंने बताया है कि विभागों की तरह कॉलेजों ने भी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया है। दौलतराम कॉलेज में रसायन विज्ञान विभाग में एससी --1 सहायक प्रोफेसर पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया। डीएवी कॉलेज सांध्य के वरिष्ठ शिक्षक प्रो.बासुकी चौधरी ने बताया है कि उनके यहाँ भी इतिहास विभाग व राजनीति विभाग में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। लेडी श्रीराम कॉलेज के हिंदी विभाग में सहायक प्रोफेसर ओबीसी --1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल किया है। इसी तरह श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ईडब्ल्यूएस पोस्ट पर नॉट फाउंड सूटेबल किया। इसी तरह से कमला नेहरू कॉलेज के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में ओबीसी --1 पद पर नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया गया। इससे पहले हंसराज कॉलेज के हिन्दी विभाग में भी अनुसूचित जनजाति (एसटी) के --01 उम्मीदवार को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया। हालांकि कॉलेज द्वारा इस पद को फिर से विज्ञापित किया गया है। डॉ. सुमन का कहना है कि अभी 80 फीसदी नियुक्ति हुई है और यदि इसी तरह से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराया जाता रहेगा तो दूसरे विभाग व कॉलेज भी इस नीति को अपना लेंगे इसलिए इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार में लगभग 600 पदों पर एडहॉक, गेस्ट टीचर्स के रूप में पढ़ा रहे शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग डीयू कुलपति से की है और कहा है कि इन कॉलेजों में नॉट फाउंड सूटेबल की प्रक्रिया को रोका जाए ताकि शिक्षा पर असर न पड़े।

डॉ.सुमन ने कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह को एक पत्र लिखा है और उन्हें बताया है कि जिन विभागों में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल किया गया है उनकी जांच कराने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर एक हाई पावर कमेटी गठित की जाए। कमेटी में दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से सेवानिवृत्त प्रोफेसर, यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय, संसदीय समिति, एससी, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन से एक-एक सदस्य के अलावा डीओपीटी/लायजन ऑफिसर होने चाहिए। यह कमेटी जांच करे कि इन पदों पर कितने उम्मीदवार साक्षात्कार के समय उपस्थित हुए, कितने अनुपस्थित, चयन समिति की मिनट्स में किस आधार पर इन अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल (एनएफएस) किया गया है। साथ ही आरक्षित श्रेणी के ऑब्जर्वर ने अपना विरोध दर्ज मिनट्स में कराया है या नहीं? इसकी जांच के बाद कमेटी सम्पूर्ण जानकारी राष्ट्रीय समाचार पत्रों व सोशल मीडिया पर दे ताकि पता चल सके कि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नॉट फाउंड सूटेबल क्यों किया जाता है?

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत नवयुवतियों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: युथ बेस डवलपमेंट सोसाइटी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत गोविन्द पूरी में 08 दिसम्बर 2024 दिन रविवार को ह्यूमनडाइजेशन प्रक्रिया चेप्टर पर कुमारी सौम्या शर्मा द्वारा नवयुवतियों को प्रशिक्षण देकर जागरूक किया गया।

इस प्रशिक्षण में शामिल सभी पार्टिसिपेंट्स ने कुमारी सौम्या शर्मा की तारीफ की और दोबारा कार्यक्रम को करने का आग्रह किया। संस्था की कोषाध्यक्ष श्रीमती मोनिका जी द्वारा कुमारी सौम्या शर्मा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

किसानों का दिल्ली कूच: पुलिस हर खतरे से निपटने को तैयार, जानिए टीकरी और सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा-व्यवस्था

किसानों के दिल्ली कूच के मद्देनजर दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। टीकरी बॉर्डर पर वॉटर कैनन समेत कई सामान मंगवाए गए हैं। सिंघु बॉर्डर पर फिलहाल कम संख्या में बल तैनात हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकता है। किसान एमएसपी कर्ज माफी पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी, MSP) के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली की ओर मार्च के मद्देनजर रविवार को दिल्ली की सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। टीकरी बॉर्डर पर तो सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहां रविवार को वॉटर कैनन (Water Canon) समेत कई सामान मंगवाए गए हैं।

वहीं, सिंघु सीमा (Singhu Border) पर फिलहाल कम संख्या में बलों को तैनात किया गया है, लेकिन बाद में पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर (Shambhu Border) पर स्थिति के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है।

टीकरी सीमा पर पानी की बौछार के लिए वॉटर कैनन तैनात।

किसानों के दिल्ली कूच को लेकर टीकरी बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन सुरक्षा कड़ी रही। हरियाणा-पंजाब बॉर्डर (Haryana-Punjab Border) पर किसानों ने रविवार को फिर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था। ऐसे में यहां पर अब वॉटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवा ली गई हैं। पुलिस के तंबू पहले से और अधिक गाड़ दिए गए हैं।

अर्ध सैनिक बल भी तैनात

पिछले किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए पुलिस के साथ-साथ अर्ध सैनिक बलों के जवान भी तैनात किए गए हैं। शंभू बॉर्डर (Shabhu Border) से टीकरी बॉर्डर आने का रूट नहीं लगता है। ऐसे में फिलहाल पुलिस को इस सीमा को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है। अगर कोई बड़ा किसान नेता ऐलान करते हैं तो बॉर्डर को बंद करने के लिए पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगेगा।

हरियाणा से दिल्ली आने वाले वाहनों की चेकिंग

वहीं, सिंघु सीमा पर रविवार को हालात तो पहले जैसे ही रहे। लेकिन यहां कुछ पुलिस के जवान वाहनों की चेकिंग करते दिखे। हरियाणा से दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों पर नजर पुलिस की नजर है। संदिग्ध लोग दिखने पर तुरंत वाहनों रोककर चेकिंग की जा रही है। फिलहाल इस सीमा पर कोई अतिरिक्त बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं।

पहले की तरह ही वाहनों की आवाजाही हो रही है। पूर्व में किसानों के दिल्ली कूच के एलान से पहले सिंघु सीमा (Singhu Border) पूरी तरह से सील कर दी गई थी। जिसके बाद सीमा खुलने के बाद दोनों सर्विस रोड से तो पूरी तरह से घेराबंदी हटा ली गई थी। लेकिन मुख्य दोनों कैरिज वे के आधे हिस्से में अभी भी जर्सी बैरियर रखे हैं। जरूरत पड़ने पर इनका दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

टीकरी पर यातायात प्रभावित होने की संभावना

टीकरी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्थाओं के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।

बता दें कि किसान एमएसपी के अलावा कर्ज माफी, किसानों एवं खेत मजदूरों के लिए पेंशन और बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग कर रहे हैं। 2020-21 में पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने की भी मांग कर रहे हैं।

रेस्तरां में खाना खाने के शौकीनों के लिए जरूरी खबर, खाने का बिल 34 हजार, विरोध पर धमकी; ऐसे चलता है पूरा धंधा

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के आरडीसी में रेस्तरां बुलाकर ठगी और उगाही के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक युवक ने इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। पिछले छह महीनों में ही चार मामले सामने आ चुके हैं। ऑनलाइन दोस्ती के बाद अनजान व्यक्ति के साथ रेस्तरां में जाने से बचें।

गाजियाबाद। आरडीसी में युवकों के साथ रेस्तरां बुलाकर ठगी और उगाही पर कविनगर पुलिस अंकुश नहीं लगा पा रही है। एक युवक ने ऐसे ही मामले में मेल पर शिकायत देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस की लापरवाही के कारण आरडीसी (Ghaziabad RDC rdc restaurant) में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। छह महीने में ही चार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं।

पीड़ति आशुतोष ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि कुछ दिन पहले वेबसाइट के जरिये शादी के लिए एक युवती संपर्क में आई। दोनों ने एक दिसंबर को मिलने की योजना बनाई। आरडीसी के हीरेज बीट कैफे में दोनों मिलने पहुंचे। पीड़ति का आरोप है कि भोजन और हुक्के का बिल 34,397 रुपये का आया।

उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ स्टाफ ने अभद्रता करते हुए धमकाया। किसी तरह उन्होंने व्यवस्था कर भुगतान किया उसके बाद पुलिस से शिकायत कर दी। पीड़ित ने ईमेल पर शिकायत भेजकर रेस्तरां संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया है।

डीसीपी सिटी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद कविनगर थाने में केस दर्ज किया गया है। मामले में शीघ्र जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

पहले भी आए ऐसे केस

हनीट्रेप में फंसाकर रेस्तरां बुलाया, 38 हजार का बिल थमाया

केस-एक

ग्रेटर नोएडा निवासी युवक अर्शलान जावेद की दोस्ती अप्रैल में टिंडर एप पर शिवि नामक युवती से हुई। युवती ने अर्शलान को 25 नवंबर को आरडीसी में मिलने के लिए बुलाया। टेस्ट आफ टेरेस रेस्तरां एवं कैफे में युवती के साथ खाने के बाद 38 हजार रुपये का बिल आया।

बिल चुकाने में युवक ने असमर्थता जताई तब बाउंसरों ने युवक के साथ अभद्रता करते हुए उसे एक कमरे में बंद कर रुपयों की व्यवस्था करने को कहा। युवक ने अपने दोस्तों से मदद ली और रेस्तरां को सात हजार रुपये चुकाकर खुद को छुड़ाकर पुलिस (ghaziabad police) से शिकायत कर दी।

केस-दो

बिल चुकाने के लिए किया ब्लैकमेल

21 अगस्त को कविनगर क्षेत्र में युवक से एक डेटिंग एप के जरिये युवती ने संपर्क करके मिलने के लिए आरडीसी के एक रेस्तरां में बुलाया। जहां सामान्य ऑर्डर के बाद उन्हें बड़ी धनराशि का बिल दे दिया गया। जिसके बाद उन्हें बिल चुकाने के लिए ब्लैकमेल किया गया।

केस-तीन

दोस्ती कर रेस्तरां बुलाया, 37 हजार का बिल थमाया

युवक को मोबाइल पर मैसेज कर एक युवती ने 20 जून को दोस्ती की फिर उसे आरडीसी में मिलने के लिए बुलाया। राजनगर एक्सटेंशन निवासी युवक गौरव कुमार आरडीसी पहुंचा तो युवती उसे क्लब लेकर गई। क्लब में खाने का बिल 37 हजार रुपये आ गया। युवक ने रुपये देने में असमर्थता जताई तो उनके साथ मारपीट की गई। किसी तरह 15 हजार रुपये देकर युवक बाहर निकला और पुलिस को मामले की शिकायत की।

ऑनलाइन हुई दोस्ती तो अनजान के साथ रेस्तरां में जाने से बचेंडीसीपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि आनलाइन दोस्ती करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती होने पर रेस्तरां में भी जाने से बचना चाहिए। समस्या होने पर तत्काल पुलिस को डायल 112 पर सूचित करें। शिकायत देकर केस जरूर दर्ज कराएं। ऐसे लोगों पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।

यूपी में राष्ट्रीय लोक अदालत के बहिष्कार का अधिवक्ताओं ने किया ऐलान, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे

परिवहन विशेष न्यूज

29 अक्टूबर को कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं ने 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है।

गाजियाबाद। कोर्ट रूम में 29 अक्टूबर को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज के मामले में शुक्रवार को भी हड़ताल जारी रही। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ताओं की मौजूदगी में एक बैठक कर अधिवक्ताओं ने 14 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का उत्तर प्रदेश में बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है।

शुक्रवार को न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के पास सुबह से ही अधिवक्ताओं का जुटना शुरू हो गया। इस दौरान बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़ सहित 22 जिलों के बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी पहुंचे।

मंच से अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि जब तक जिला जज का निलंबन नहीं होता है, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गाजियाबाद के सभी अधिवक्ता हड़ताल में शामिल होकर एकजुट होकर आंदोलन को तेज बनाएंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के दौरान कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं होंगे।

एलएलबी की फर्जी डिग्री मामले में आप के लीगल हेड पर बीयीअसई की कार्रवाई, बीसीडी उपाध्यक्ष पद से हटाया

परिवहन विशेष न्यूज

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आम आदमी पार्टी (AAP) के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। नासियार की एलएलबी (ऑनर्स) डिग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध पाई गई है। BCI ने डिग्री की प्रामाणिकता की जांच के लिए CBI से संपर्क किया है। जांच पूरी होने तक नासियार को उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।

जागरण संवाददाता, कानून की डिग्री की प्रामाणिकता की जांच पूरी होने तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई, BCI) ने वरिष्ठ अधिवक्ता और आम आदमी पार्टी (AAP) के लीगल सेल के हेड संजीव नासियार को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी, BCD) के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है।

नासियार के पास इंदौर के देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री है।

बीसीआई ने रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि उसके द्वारा गठित उप-समिति ने गहन जांच के बाद निष्कर्ष निकाला कि संजीव नासियार की एलएलबी (ऑनर्स) डिग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है।

डिग्री की प्रमाणिकता की होगी जांच

यह भी कहा कि बीसीआई की सामान्य परिषद ने बीसीआई सचिव को डिग्री की प्रामाणिकता की जांच करने का अनुरोध करते हुए सीबीआई से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। बीसीआई सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा हस्ताक्षर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जांच के नतीजे आने तक संजीव नासियार (Sanjeev Nasiar) तक बीसीआई के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है।

यह विडियो भी देखें

उन्होंने कहा कि कानूनी पेशे की अखंडता और गरिमा की रक्षा करने के साथ ही जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए यह उपाय आवश्यक था। इस मामले में जांच अधिवक्ता नरेश चंद्र गुप्ता की याचिका के बाद शुरू हुई थी, उन्होंने नसियार पर फर्जी एलएलबी डिग्री के आधार पर पंजीकरण कराने का दावा किया था।

ाजपा ने साधा निशाना

वहीं, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि अधिवक्ता संजीव नसीयार की डिग्री को लेकर विवाद बिल्कुल जितेंद्र सिंह तोमर के डिग्री विवाद जैसा है। उनके भी बिहार के कॉलेज में कानून पढ़ाने की अनुमति नही थी और आज ऐसा ही विवाद इंदौर के उस कॉलेज को लेकर भी सामने है। जहां की डिग्री से संजीव नसियार खुद को वकील बताते है।

उन्होंने कहा कि संजीव नसीयार को उनकी कानून की शैक्षणिक डिग्री को लेकर विवाद के चलते बार काउंसिल आफ दिल्ली से पदमुक्त करने का पत्र सामने आया तो केजरीवाल के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमार की फर्जी डिग्री का मामला लोगों की यादों में ताज़ा हो गया।

इससे दिल्ली वाले हैरान है कि आप नेताओं के फर्जी डिग्री के मामले लगातार सामने आ रहे है। भाजपा लीगल प्रकोष्ठ संयोजक अधिवक्ता नीरज ने कहा है की बार काउंसिल आफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, जिसकी निषपक्षता एवं कार्य पारदर्शिता बहुत ही उच्च स्तर की है।

फरीदाबाद एयरफोर्स स्टेशन के पास उड़ते मिला संदिग्ध विमान, मची हलचल

फरीदाबाद के एयरफोर्स स्टेशन के आसपास एक छोटे वायुयान के लगातार चक्कर लगाने से हड़कंप मच गया है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले की सूचना एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों को लग गई। उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया।

फरीदाबाद। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास छोटे वायुयान द्वारा लगातार कई चक्कर लगाने की सूचना से हलचल रही। पता चला है कि शक इसलिए अधिक गहराया जब वायुयान ने एक ही जगह के कई चक्कर लगाए। किसी ने इसका वीडियो बनाया और इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया।

एक से दूसरे और पर वीडियो पहुंची तो इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची। सारन थाना प्रभारी संदीप ने पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी से एक टीम ने मौका मुआयना करने के लिए कहा। टीम एयरफोर्स स्टेशन पहुंची और इस बारे में पता किया।

अधिकारियों ने क्या कहा

इस मामले की सूचना एयरफोर्स स्टेशन के अधिकारियों को लग गई। उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। अब वह भी अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। वीडियो कपड़ा कॉलोनी की साइड की बताई जा रही है। इस बारे में उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है।

पुलिस को नहीं मिली कोई शिकायत

पुलिस के पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। फिर भी जांच में जुटी है। यह भी पता किया जा रहा है कि वीडियो किसने बनाई। पता चला है कि एक युवक रविवार को छत पर धूप सेक रहा था। अचानक ऊपर बिना आवाज के एक छोटा वायुयान उड़ते हुए देखा।

थोड़ी दूर जाकर फिर उसी जगह आ गया। इस तरह कई चक्कर लगाए। शक हुआ कि बिना आवाज के इतना सा वायुयान क्यों चक्कर लगा रहा है।

आगामीं केंद्रीय बज़ट 2025-26 की कवायद शुरू -11 वर्गों से प्री बजट कंसल्टेशन शुरू

बज़ट 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित होने की संभावना-हर वर्ग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की उम्मीद

जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने में आम जनता हितधारकों के सुझाव ज़रूरी-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर दुनियाँ के हर देश को विकसित देश बनाने का मुख्य आधार उस देश का बजट दस्तावेज है,जो उस देश की वित्तीय रणनीति का दस्तावेज होता है। यानें उस देश के शासन को विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से देश चलाने के लिए पैसों का इंतजाम क़र जरूरत के अनुसार उन्हें उसका एलोकेशन, बजट ही करता है जो अति चुनौती भरा कार्य है,क्योंकि मैं टैक्सेशन क्षेत्र से हूं तो मैं बजट का गहराई से विश्लेषण कर उसकी चुनौतियों को नज़दीकी से देखता हूं, क्योंकि किस तरह और कैसे दो माह पूर्व से ही बज़ट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है व अति गोपनीयता से बजट बनाया जाता है। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि भारत में 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट की कवायत 6 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है।6 दिसंबर को अर्थशास्त्रियों,विशेषज्ञों के साथ व 7 दिसंबर 2024 को किसानों व उनके प्रतिनिधियों के साथ माननीय वित्तमंत्री व वित्तमंत्रालय के सहयोगियों बैठक के संपन्न हुई,अब 30 दिसंबर को भारतीय इंडस्ट्री व कौशलता क्षेत्र एजुकेशन व हेल्थ केयरों के जानकारों के साथ बैठक कर उनके सुझाव व विचार जान जाएंगे, यानें क़रीब 11 अलग- अलग क्षेत्रों से बैठकें की जाएगी, फिर नोटिफिकेशन जारी कर आम जनता से सुझाव मांगे जाएंगे, फिर बजट लिखना शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 फरवरी 2025 तक के अंतिम 10 दिनों पूर्व बजट बनाने वाली टीम का नाता दुनियाँ से कट जाता है,यानें गुप्त रूप में बजट बनाया जाता है,जिसमें किसी भी प्रकार के संचार माध्यमों से उनका नाता बिल्कुल नहीं होता। चूँकि बजट 2025-26 पर माथापच्ची दिनांक 6 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुकी है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 की कवायद शुरू, 11 वर्गों से प्री बजट कंसल्टेशन शुरू, 1 फरवरी 2025 को बज़ट पेश होने की संभावना।

साथियों बात अगर हम 6 दिसंबर 2024 कोअर्थशास्त्रियों वित्त विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक की करें तो,बजट 2025 -26 की तैयारी शुरू हो गई है और इसको लेकर वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया हैं। बजट एक फरवरी, 2025 को संसद में पेश किये जाने की संभावना है।6 दिसंबर यानें शुक्रवार से वित्तमंत्री ने बजट-पूर्व परामर्श यानी प्री-बजट कंसलटेशन शुरू कर दिया है। वित्त मंत्रालय में बजट बनाने की प्रक्रिया के तहत कई सालों से ये परंपरा चली आ रही है, कंसलटेशन की इस सीरीज के तहत छह दिसंबर को देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के साथ पहली बैठक की गई है।अब 30 दिसंबर को भारतीय इंडस्ट्री के प्रमुख और सोशल सेक्टर के गणमान्य व्यक्तियों, खास तौर से एजूकेशन और हेल्थकेयर के हितधारकों के परामर्श के साथ बजट पूर्व परामर्श खत्म होगा। 2025-26 के आम बजट पर उनके विचार मांगे जाएंगे और कुल सुझावों और सिफारिशों,इन बैठकों में वित्तमंत्री के अलावा वित्त राज्यमंत्री , वित्त सचिव और निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) सचिव,आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव और वित्तीय सेवा सचिव की मौजूदगी रहेगी।

साथियों बात अगर हम 7 दिसंबर 2024 को कृषि हित धारकों प्रतिनिधियों विशेषज्ञों से बैठक की करें तो शनिवार को बजट से पहले होने वाली बैठकों के क्रम में किसान प्रतिनिधियों और कृषि हितधारकों के साथ बैठक की। इस दौरान किसानों ने सरकार से सस्ता दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने, कम कर लागू करने और पीएम- किसान आय सहायता को दोगुना करनेकिसानों की मुख्य मांगों में कृषि ऋणों पर ब्याज दर को एक प्रतिशत तक कम करना और वार्षिक पीएम- किसान किस्त को 6 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 12हज़ार रुपए करना शामिल था हितधारकों ने इसके अलावा कराधान सुधार प्रस्तावों के तहत कृषि मशीनरी, उर्वरक, बीज और दवाओं पर जीएसटी छूट की मांग की, बैठक में दो घंटे तक विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान वित्तीय राहत, बाजार सुधार और रणनीतिक निवेश जैसी कृषि क्षेत्र की कई चुनौतियों का समाधान करने पर विचार किया गया। भारत कृषक समाज के चेयरमैन ने कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की जरूरत पर जोर दिया। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कीटनाशक पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का अनुरोध किया।राष्ट्रीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए चना, सोयाबीन और सरसों जैसी विशिष्ट फसलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आठ वर्षों के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपए की लक्षित निवेश रणनीति का प्रस्ताव रखा।

साथियों बात अगर हम केंद्रीय बजट तैयार करने की करें तो यह बहुत कठिन और बाहरी बैठकों, सुझावों के अतिरिक्त 5 चरणों में होता है जिसकी गतिविधियां बहुत पहले शुरू हो जाती है। हमें 1 फरवरी को बजट मिल जाता है लेकिन इसके पीछे कितनीमेहनत और कठिनाई में शामिल है। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग; उद्योग, अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन; वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार; सेवा और व्यापार क्षेत्र; सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ; ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल होते हैं । हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए कई सुझाव जिनमें एमएसएमई की मदद के लिए हरित प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आयकर को तर्कसंगत बनाना, नवाचार क्लस्टरों का निर्माण करना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर करने के लिए योजनाएं बनाना, इत्यादि शामिल हैं।आते हैं।वित्त मंत्री ने प्रतिभागियों द्वारा अपने बहुमूल्य सुझावों को साझा करने के लिए उनका धन्यवाद कियाजाता हैं और आश्वासन दिया जाता कि बजट 2025-26 तैयार करते समय इन सुझावों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा।बता दें, आगामी बजट के लिए बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने सोशल सेक्टर जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पानी और साफ- सफाई की व्यवस्था से जुड़े जानकारों के साथ मुलाकातकरती हैं । वहीं, इससे सेवा एवं व्यापार क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ भी प्री-बजट होंगी ।केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित करेंगी , जिसे अगले साल फरवरी में पेश किया जाएगा। जिसके लिए माय गोव प्लेटफार्म से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे।जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक मामलों का विभाग वित्त मंत्रालय बजट बनाने की प्रक्रिया को सहभागी और समावेशी बनाने के लिए हर साल नागरिकों से सुझाव आमंत्रित करता है, जो भारत को समावेशी विकास के साथ वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने में मदद कर सकते हैं।

साथियों बात अगर हम बजट बनाने वाले स्टॉफ़ अधिकारियों की करें तो, बता दें कि 10 दिनों तक दुनियाँ से दूर अपने काम को अंजाम देने में जुटे कम से कम 100 अधिकारियों और कर्मचारियों को इस अवधि में अपने घर जाने की भी इजाजत नहीं होती है। बजट तैयार होने के दौरान वित्त मंत्री के बेहद वरिष्ठ और भरोसेमंद अधिकारियों को ही घर जाने की इजाजत होती है। जब तक बजट पेश नहीं हो जाता तब तक बजट तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर इस दौरान वित्त मंत्रालय की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होती है। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश वित्त मंत्रालय में नहीं होता है। इस दौरान छपाई से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों को भी बाहर आने या फिर अपने सहयोगियों से मिलने की भी मनाही होती है। अगर किसी विजिटर का आना बहुत जरूरी है तो उन्हें सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में अंदर भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय में खुफिया विभाग से लेकर के साइबर सिक्योरिटी सेल सबका पहरा रहता है। इन 10 दिनों तक मंत्रालय के अंदर कोई भी मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। केवल लैंडलाइन फोन के जरिए ही बातचीत हो पाती है।दरअसल, यह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था इस लिए की जाती है ताकि देश के वित्तीय लेखा-जोखा को तैयार करने के दौरान कोई भी अंदरूनी जानकारी किसी भी तरह से लीक न हो सके। यह वजह है कि इस कार्य में जुटे सभी अधिकारी और कर्मचारियों को कड़ी निगरानी के बीच बाहर की दुनिया से दूर रहना पड़ता है। वित्त मंत्रालय में 10 दिन के लिए डॉक्टरों की एक टीम भी तैनात रहती है। ऐसा इसलिए ताकि किसी भी कर्मचारी के बीमार पड़ने पर उसे वहीं पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बीमार कर्मचारी को भी 10 दिनों के लिए अस्पताल में इलाज कराने की मनाही होती है। यह इस बात का उदाहरण है कि देश का बजट तैयार करना आसान बात नहीं, बल्कि हर बारीकियों पर बेहद सतर्कता के साथ निगरानी की जाती है ताकि देश के बजट से जुड़ी जानकारियों पूरी तरह से गोपनीय रहें और इन्हें बजट पेश होने से पहले कोई न जान सके। बजट तैयार होने के दौरान आखिरी के 10 दिनों में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहती है। जिन कंप्यूटरों पर बजट डॉक्यूमेंट मौजूद होता है, उनसे इंटरनेट और एनआईसी के सर्वर को डिलिंक कर दिया जाता है। इससे किसी भी प्रकार की हैकिंग का डर नहीं रहता है। इन कंप्यूटरों को केवल प्रिंटर और छपाई मशीन से कनेक्ट करके रखा जाता है। वित्त मंत्रालय के जिस हिस्से में प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, वहां पर केवल चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को जाने की इजाजत होती है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आगामीं केंद्रीय बज़ट 2025-26 की कवायद शुरू-11 वर्गों से प्री बजट कंसल्टेशन शुरू-1 फ़रवरी 2025 को बज़ट पेश होने की संभावना।बज़ट 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर केंद्रित होने की संभावना- हर वर्ग के सुझाव पर गंभीरता से विचार करने की उम्मीद।जनभागीदारी की भावना को बढ़ावा देने, समावेशी विकास के साथ भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने में आम जनता, हितधारकों के सुझाव ज़रूरी हैं।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

जयपुर में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना

परिवहन विशेष न्यूज

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जयपुर दूसरे राज्यों के नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इन वाहनों के मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटरों को पत्र भेजा है। इन सेंटरों को दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आरटीओ संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे शहर में लगातार वाहन का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान की सीमा से लगे दूसरे राज्यों के जिलों में वाहनों पर टैक्स 5 प्रतिशत तक है। राजस्थान में यह 12 प्रतिशत तक है। टैक्स बचाने के लिए लोग दूसरे राज्यों से वाहन खरीदकर जयपुर में चलाते हैं। जयपुर में ऐसे 10 हजार से ज्यादा वाहन सड़क पर दौड़ रहे हैं।

मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार दूसरे राज्य से एक महीने से ज्यादा समय तक वाहन चलाने पर टैक्स देना होता है। सभी सर्विस सेंटरों से डाटा मिलने के बाद इनकी जांच की जाएगी। आरटीओ जयपुर प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा- हमने सभी सर्विस सेंटरों से डाटा मांगा है। अगर वाहन मालिक यह सबूत नहीं दे पाते कि वाहन रोजाना शहर में नहीं चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नियमानुसार अगर वाहन संचालन के दौरान टैक्स जमा नहीं कराया गया है। ऐसे वाहन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर में सभी वाहन वैध तरीके से संचालित हों। आरटीओ की इस कार्रवाई से ऐसे वाहन मालिकों को चेतावनी दी गई है जो नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। इस कदम से राज्य सरकार का राजस्व सुरक्षित होगा।

टैक्स की राशि वाहन के प्रकार, वजन, मॉडल और उपयोग के आधार पर तय होती है। कमर्शियल वाहनों के लिए अलग से पैसा तय होता है, जो निजी वाहनों से ज्यादा होता है। टैक्स जमा होने के बाद वाहन मालिक को उसकी वैधता के हिसाब से रसीद मिलती है।

अगर वाहन मालिक समय पर टैक्स जमा नहीं कराता है तो उसे रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की राशि वाहन के प्रकार और टैक्स के बकाया समय पर निर्भर करती है। जयपुर आरटीओ ने वाहन मालिकों को टैक्स भुगतान में देरी न करने और डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग करने का सुझाव दिया है।

कटिहार में रूट चार्ट के आधार पर ई-रिक्शा परिचालन की कवायद में

परिवहन विशेष न्यूज

कटिहार परिवहन विभाग रूट चार्ट के आधार पर ई-रिक्शा परिचालन करने जा रहा है। जिसको लेकर परिवहन विभाग इस मुद्दे पर मंथन कर वरीय अधिकारी के आदेश का इंतजार कर रहा है। जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रिक्शा की भरमार है। जिसके कारण शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवे, मुख्य सड़क समेत सभी बाजार की सड़कों व गली-मोहल्लों में ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जाता है। एक रूट पर अधिक ई-रिक्शा चलने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। ऐसे में परिवहन विभाग यातायात व्यवस्था को सुधारने की दिशा में पहल करते हुए रूट चार्ट के आधार पर ई-रिक्शा चलाने का प्रयास कर रहा है।

परिवहन विभाग द्वारा दिए गए आंकड़ों की मानें तो जिले में करीब सात हजार निर्बंधित ई-रिक्शा परिचालन कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में ई-रिक्शा की संख्या अधिक है। जिसके कारण शहर के सभी मुख्य सड़कों व बाजारों में ई-रिक्शा की भरमार है। शहर में जाम की समस्या तब उत्पन्न होती है, जब एक ही सड़क पर ई-रिक्शा का दबाव अधिक हो जाता है। जबकि सैकड़ों ई-रिक्शा बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। ऐसे में जिले में करीब आठ से नौ हजार ई-रिक्शा चल रहे हैं। ई-रिक्शा में बढ़ोतरी का कारण यह है कि निजी फाइनेंस कंपनियां कम डाउन पेमेंट पर लोगों को वाहन उपलब्ध कराती हैं। जिसकी ईएमआई ई-रिक्शा चलाकर आसान किस्तों में चुकाई जाती है। जिसके कारण ई-रिक्शा की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चालक, ठेला चालक भी ई-रिक्शा चलाने लगे हैं। यहां तक कि दुकानों में काम करने वाले युवा, निजी फर्मों में निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मी, यहां तक कि वे बेरोजगार युवा भी जिन्हें काम नहीं मिला है। वे काम की तलाश में हैं। ऐसे में ई-रिक्शा उनकी भी पसंद बन गया है। यही कारण है कि ई-रिक्शा की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिसके कारण शहर की कई सड़कें ई-रिक्शा से भर गई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को ई-रिक्शा के संचालन को लेकर कोई ठोस पहल करनी चाहिए। ताकि शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे।

जिला परिवहन पदाधिकारी बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि जिले में करीब सात हजार ई-रिक्शा का परिचालन हो रहा है। ई-रिक्शा के परिचालन से शहर में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। जाम से निपटने के लिए रूट चार्ट के आधार पर ई-रिक्शा का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

एमजी मोटर की कॉमेट ईवी और विंडसर ईवी जनवरी से हो जाएंगी महंगी

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली एमजी मोटर ने अगले महीने 2025 से अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा की है। इनमें कंपनी के इलेक्ट्रिक वाहन भी शामिल होंगे। एमजी मोटर के ईवी पोर्टफोलियो में कॉमेट ईवी, विंडसर ईवी और जेडएस ईवी शामिल हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा है कि बढ़ती इनपुट लागत और अन्य कारणों से वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करना जरूरी हो गया है। इसके साथ ही एमजी मोटर का कहना है कि ग्राहकों पर मूल्य वृद्धि का असर कम से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। ईवी के अलावा उसने एस्टोर, हेक्टर और ग्लोस्टर जैसी एसयूवी की कीमतों में भी बढ़ोतरी करने की योजना बनाई है। मॉडल के आधार पर कीमतों में तीन फीसदी तक बढ़ोतरी होगी। पिछले महीने कंपनी की बिक्री में करीब 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसमें ईवी की हिस्सेदारी 70 फीसदी से ज्यादा रही।

एमजी मोटर की कॉमेट ईवी देश की सबसे कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी की विंडसर नवंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी रही है। पिछले महीने एमजी मोटर की कुल बिक्री 6,019 यूनिट रही। नवंबर में एमजी मोटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 5,092 यूनिट रही। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स पहले स्थान पर है। एमजी मोटर ने अक्टूबर में विंडसर ईवी की 3,116 यूनिट बेचीं। कंपनी ने दशहरे पर इस इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर की डिलीवरी ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। इसकी कीमत करीब 13.50 लाख रुपये से लेकर 15.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।

यह पहली ईवी है जिसके लिए बैटरी एज ए सर्विस का विकल्प दिया गया है। इसमें विंडसर ईवी की शुरुआती कीमत घटकर करीब 10 लाख रुपये रह जाएगी। हालांकि इसके साथ 3.5 रुपये प्रति किलोमीटर अतिरिक्त बैटरी किराया देना होगा। इसकी बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे के अंदर ही एमजी मोटर को 15,000 से ज्यादा बुकिंग मिल गईं। यह क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल सेडान जैसा आराम और एसयूवी जैसा स्पेस देती है। विंडसर ईवी तीन वेरिएंट में उपलब्ध है - एक्साइट, एक्सक्लूसिव और एसेंस। इसका मुकाबला महिंद्रा XUV400 और टाटा मोटर्स की नेक्सन ईवी से है। पिछले कुछ सालों में ईवी की बिक्री में तेज़ी से इज़ाफा हुआ है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां इस सेगमेंट में अपने मॉडल पेश कर रही हैं।

जेबीएम ग्रुप और केपेल ने टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचे के लिए की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

शहरी बुनियादी ढांचे के डीकार्बोनाइजेशन में नवाचार को प्रोत्साहित करने और इलेक्ट्रो-मोबिलिटी, बढ़ती मांग के कारण होने वाले इलेक्ट्रिक कचरे और वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में हरित बिजली के अवसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करने के लिए जेबीएम समूह और केपेल लिमिटेड द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जेबीएम समूह इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवी एग्रीगेट्स के साथ-साथ इलेक्ट्रो मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ-साथ ई-वेस्ट सॉल्यूशंस से संबंधित परियोजनाओं को विकसित करने में प्रमुख ऑटो सिस्टम में अपनी ताकत का निर्माण करेगा। केपेल एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा, ईवी चार्जिंग और संसाधन सर्कुलरिटी विशेषज्ञता में सर्वोत्तम अभ्यास ज्ञान को साझेदारी में आगे बढ़ाता है।

जेबीएम ग्रुप के उपाध्यक्ष निशांत आर्य के अनुसार, यह रणनीतिक गठबंधन दुनिया भर में ऊर्जा समाधानों को बदलने और राष्ट्रों और राज्यों को उनके डीकार्बोनाइजेशन मील के पत्थर हासिल करने में योगदान देने में मदद करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कंपनियाँ नए प्रतिमान विकसित करके स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रो-मोबिलिटी क्षेत्रों में दूरदर्शी प्रभाव प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, जिनमें वैश्विक स्थिरता प्रयासों को नेट जीरो की ओर ले जाने की क्षमता है।

केपेल के इंफ्रास्ट्रक्चर डिविजन की सीईओ सिंडी लिम ने कहा कि भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, शहरीकरण और विद्युतीकरण के कारण बिजली की जरूरतें बढ़ रही हैं। इससे केपेल जेबीएम ग्रुप जैसे प्रमुख भागीदारों के मार्गदर्शन में भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

बजाज के एमडी राजीव बजाज ने ओला को ट्रोल करते हुए कहा, "ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है

परिवहन विशेष न्यूज

सीएनबीसी के एक कार्यक्रम में बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने ओला को ट्रोल करते हुए कहा, ₹ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है।₹ चेतक बजाज का इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर है और बजाज ने कहा कि यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बन गया है। ₹मेरा बेटा ऋषभ जो पिछले 2.5 सालों से इलेक्ट्रिक चेतक टीम का हिस्सा है, उसने मुझे बताया कि दिसंबर वाहन रजिस्ट्रेशन डाटा के आधार पर हमारा इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक अब तीसरा सबसे बड़ा नहीं बल्कि देश में सबसे ज्यादा बिकने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है।₹ राजीव बजाज ने इस अपडेट के बाद ओला इलेक्ट्रिक पर कटाक्ष करते हुए कहा, ₹ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है।"

राजीव बजाज की यह टिप्पणी नवंबर के आंकड़ों के बाद आई है जिसमें दिखाया गया है कि ओला की बाजार हिस्सेदारी तीन महीनों में सबसे कम हो गई है और बजाज और टीवीएस इसके ठीक पीछे हैं। नवंबर माह में वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार ईवी दोपहिया वाहनों में ओला की हिस्सेदारी 24.5 प्रतिशत थी। इसके बाद टीवीएस की हिस्सेदारी 23 प्रतिशत और बजाज की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत थी।

हाल के महीनों में ओला की बाजार हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। जून में इसकी बाजार हिस्सेदारी 49 प्रतिशत थी, जो जुलाई में घटकर 39 प्रतिशत, अगस्त में 32 प्रतिशत और सितंबर में 27 प्रतिशत रह गई। अक्टूबर में ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी मामूली रूप से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गई, लेकिन अब नवंबर में घटकर 24 प्रतिशत रह गई है।

यही वह क्षण है जब बजाज 22 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ ओला से ठीक पीछे है का यह कहना चुना है कि ₹ओला तो ओला है, चेतक तो शोला है₹। यह पहली बार नहीं है जब राजीव बजाज ने ओला को ट्रोल किया है। 2021 में राजीव बजाज ने कहा था कि बजाज ओला जैसी कंपनियों को नाश्ते में खा जाएगा। उन्होंने कहा था, ₹हम चैंपियन हैं और चैंपियन नाश्ते में ओट्स का इशारा यानी ओला, एथर, टॉर्क मोटर्स और स्मार्टई जैसे स्टार्टअप के लिए एक संक्षिप्त नाम से मेल खाते हैं।₹

ओला भी बजाज पर सीधे हमला कर रही है। यह दावा करते हुए कि ओला आईसी इंजन युग को समाप्त कर देगी। आईसी इंजन आंतरिक दहन इंजन है, जो पेट्रोल और डीजल वाहनों को शक्ति प्रदान करता है और ओला कह रही है कि यह अपने स्वयं के इलेक्ट्रिक ऑफरिंग के साथ बजाज के अधिकांश पोर्टफोलियो को विलुप्त कर देगी। यह देखना बाकी है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर युद्ध कैसे आगे बढ़ता है लेकिन फिलहाल इस

ग्रामीण महिलाओं को सीसीएल ने दिया ई-ऑटो

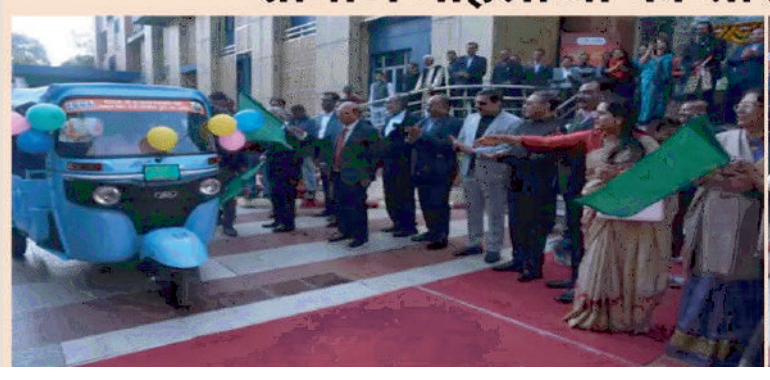

सीसीएल, रांची ने सीएसआर के तहत महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। आरके मिशन टीबी सैनिटोरियम के लिए 10 ई-ऑटो का वितरण किया। इसे सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह और अन्य गणमान्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ई-ऑटो वितरण का उद्देश्य टीबी मरीजों और अन्य रोगियों को अस्पताल परिसर के अंदर और उसके आसपास परिवहन सेवाएं प्रदान करना है। यह पहल वंचित महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर भी प्रदान करती है। इस परियोजना के तहत 10 महिलाओं को ई-ऑटो चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। रामकृष्ण मिशन के निर्देशन में उनकी निगरानी की जाएगी। ये महिलाएं प्रतिदिन 500 रुपये तक की आय अर्जित करेंगी। यह पहल महिलाओं के लिए आजीविका के स्थायी साधन के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने की दिशा में सहायक होगा। ई-ऑटो प्राप्त करने वाली महिलाओं ने सीसीएल और रामकृष्ण मिशन का आभार व्यक्त किया। इस परियोजना को 'जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली' पहल बताया। इस अवसर पर सीएमडी सीसीएल नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रामकृष्ण मिशन के सहयोग से संचालित यह परियोजना टीबी एवं अन्य मरीजों के लिए परिवहन सेवाओं को सस्ता और सुविधाजनक बनाएगी।

कार्य और अध्ययन- एक सिंहावलोकन

विजय गर्ग

पढ़ाई के साथ-साथ काम करना कोई नई अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा पश्चिमी देशों में काफी समय से सफल रही है लेकिन हमारे देश में यह एक नई अवधारणा है। पश्चिमी देशों में लगभग 60% छात्र ऐसे हैं जो अपनी उच्च शिक्षा का खर्च स्वयं उठाते हैं। हालाँकि आपकी उच्च शिक्षा फीस की पूरी राशि का योगदान करना संभव नहीं है, फिर भी पढ़ाई के दौरान काम करने से एक छात्र को अपनी शिक्षा में कम से कम कुछ योगदान करने में मदद मिल सकती है। हालाँकि यह कई लोगों के लिए बड़ी रकम नहीं हो सकती है, फिर भी इसमें शामिल आनंद और संतुष्टि की मात्रा अन्य सभी तथ्यों पर भारी पड़ती है। पढ़ाई के दौरान काम करना दो तरह से हो सकता है: कॉलेज में कार्य-अध्ययन का विकल्प अंशकालिक नौकरी पहला विकल्प कार्य-अध्ययन कार्यक्रम को चुनना है। यदि आप किसी कार्य-अध्ययन कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो आप परिसर में प्रदान की गई अपनी सेवा के लिए धन और प्रति घंटा वेतन प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता के आधार पर किसी भी सीमा तक हो सकता है। कार्य-अध्ययन के लिए कई अलग-अलग अवसर हैं, इसलिए छात्रों के लिए उनके विषय से संबंधित कुछ खोजने का अच्छा मौका है। छात्रों को या तो कॉलेज या विश्वविद्यालय, किसी राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय सार्वजनिक एजेंसी द्वारा नियोजित किया जा सकता है; एक निजी गैर-लाभकारी संगठन; या एक निजी लाभकारी संगठन। ऐसी भी संभावना है कि छात्रों को सामुदायिक शिक्षण कार्यक्रमों में लिए काम करने के लिए कहा जा सकता है जो कुछ कमाई के अनुभव के साथ-साथ कुछ प्रकार की आंतरिक संतुष्टि भी देते हैं। पढ़ाई के दौरान काम का एक अन्य विकल्प ऑफ-कैंपस अंशकालिक या पूर्णकालिक नौकरी हो सकता है। हालाँकि पूर्णकालिक पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्र पूर्णकालिक नौकरी के लिए नहीं जा सकते हैं, फिर भी वे अंशकालिक नौकरी का प्रबंधन कर सकते हैं जो इन दिनों युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है। यह अंशकालिक नौकरी आपके प्रमुख विषयों से संबंधित नौकरी या कौशल से संबंधित नौकरी से भिन्न हो सकती है। इन दिनों देश भर के कॉल-सेंटरों में बहुत सारी अंशकालिक नौकरियां उपलब्ध हैं, जिसने भारतीय बाजार में एक क्रांति की तरह प्रवेश किया और कम समय में बड़ी लोकप्रियता हासिल की। कॉलेज के छात्रों के लिए अन्य नौकरियां ट्यूशन कक्षाएं, ऑनलाइन नौकरियां आदि आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम लेना हो सकता है। विशिष्ट कार्य-अध्ययन नौकरियों कार्य-अध्ययन वाली नौकरियाँ पाना और निष्पादित करना कठिन नहीं है। इनमें कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं जिन्हें छात्र आसानी से कर सकते हैं। हालाँकि भारत में ऐसे बहुत से कॉलेज नहीं हैं जो छात्रों को कार्य-अध्ययन का विकल्प प्रदान कर रहे हों, फिर भी यह अवधारणा भारत में भी लोकप्रिय हो रही है। यदि आपको कैंपस में कार्य-अध्ययन की नौकरी मिलती है, तो आपका कॉलेज आमतौर पर आपका नियोक्ता होगा। छात्रों के लिए विशिष्ट नौकरियों में पुस्तकालय या किताबों की दुकान में काम करना, डाइनिंग हॉल में अन्य छात्रों की सेवा करना और कॉलेज के कार्यक्रमों में सहायता करना शामिल है। ऑफ-कैंपस काम आम तौर पर किसी न किसी तरह से जनता को लाभान्वित करता है और जितना संभव हो सके आपके अध्ययन के पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। आप गुरु गाइड को नौकरी भी तलाश सकते हैं। छात्र कार्य-अध्ययन कार्यक्रम में नहीं बल्कि अन्य साथी छात्रों के साथ काम कर सकता है। वास्तव में, सभी मामलों में, आपका रोजगार किसी भी अन्य नौकरी के समान ही दिखाई देगा। केवल कॉलेज और आपके नियोक्ता को ही पता चलेगा कि आप एक कार्य-अध्ययन छात्र हैं। नियमित अंशकालिक नौकरी और कार्य-अध्ययन नौकरी के बीच एकमात्र अंतर यह है कि आपके वेतन का कुछ हिस्सा सरकार, राज्य, आपके कॉलेज या किसी अन्य संगठन द्वारा कवर किया जा सकता है। उन छात्रों के लिए भी एक विकल्प उपलब्ध है जो स्कूल वर्ष के अंत से पहले अपनी कार्य-अध्ययन नौकरी छोड़ने का निर्णय लेते हैं, या जिन्हें कार्य-अध्ययन नौकरी नहीं मिल पाती है, वे अपनी कार्य-अध्ययन सहायता को ऋण में बदल सकते हैं। हालाँकि, यह कॉलेज के हिसाब से भिन्न हो सकता हैकालेज के लिए। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान काम करने के फायदे और नुकसान कुछ छात्रों के लिए, कॉलेज में काम करना एक आवश्यकता है; संभवतः कम संपन्न परिवारों के ऐसे छात्र हैं जो अपने शैक्षिक खर्चों का समर्थन करने का निर्णय लेते हैं जबकि दूसरों के लिए यह केवल एक इच्छा है। आर्थिक रूप से मजबूत परिवारों के कुछ छात्र भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए काम करने का निर्णय लेते हैं। कई छात्रों को कॉलेज में रहने के दौरान काम करना पड़ता है, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो वे पहली बार में कोर्स करने में सक्षम नहीं होंगे। हालाँकि, जिनके पास कोई विकल्प होता है उन्हें एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज में रहते हुए काम करने के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। इसलिए, अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले तर्क के दोनों पक्षों पर विचार करना आवश्यक है। हालाँकि, कारण जो भी हो, नौकरी लेने के लिए सहमत होने से पहले कॉलेज में काम करने के फायदे और नुकसान को जानना महत्वपूर्ण है, इसमें निम्नलिखित पहलू शामिल हो सकते हैं: कॉलेज में पढ़ाई के साथ काम करने के फायदे जीवन का आनंद लेने के लिए अधिक पैसा: यह एक तथ्य है कि लगभग 50% छात्रों ने कुछ पैसे कमाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए कार्य-अध्ययन कार्यक्रम में दाखिला लिया। सबसे पहले कॉलेज को वित्त पोषित करने के लिए धन की आवश्यकता के अलावा, थोड़ा अतिरिक्त पैसा एक ऐसी चीज है जो हर छात्र की इच्छा होती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हर कोई अपने कॉलेज जीवन के दौरान खर्च करना चाहता है, जिसमें दावतों पर खर्च करना और छुट्टियों में यात्रा करना जीवन को बहुत आसान बना सकता है। कम बजट में जीवन जीना असंभव नहीं है, लेकिन हाथ में कुछ नकदी हो तो यह और भी मजेदार है। और अपने खुद के कमाए हुए पैसे को खर्च करने में बहुत खुशी मिलती है। व्यावसायिक विकास: पढ़ाई के साथ-साथ काम करने से आपको पेशेवर जीवन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मिलती है। कैंपस में कोई भी नौकरी छात्रों को संचार (मौखिक और लिखित), टीम वर्क, समय प्रबंधन और ग्राहक सेवा जैसे पेशेवर कौशल सीखने का अवसर प्रदान कर सकती है, साथ ही एक पेशेवर नेटवर्क बनाने के अवसर भी प्रदान कर सकती है। छात्रों को कुछ अच्छे कामकाजी अनुभव प्राप्त होते हैं और साथ-साथ पेशेवर व्यवहार भी सीखने को मिलता है। बहुत से छात्र स्नातक के बाद अपने शैक्षणिक जीवन के बाहर बहुत कम अनुभव के साथ नौकरी बाजार में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं और कभी-कभी अनुभव की कमी के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ सकता है। आजीविका के लिए काम करने से, यहां तक कि अंशकालिक आधार पर भी, कुछ कौशल विकसित होते हैं जिनकी पेशेवर जीवन में आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें अध्ययन के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है - सरल चीजें जैसे कि विभिन्न लोगों के साथ कैसे संवाद करें और नौकरी के लिए साक्षात्कार में कैसे व्यवहार करें . इससे ग्रेजुएशन के बाद काम पर जाना बहुत आसान और प्रभावी तरीके से हो जाता है। ऋण से मुक्तिः बहुत से छात्रों को अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए ऋण का विकल्प चुनना पड़ता है, जिसे उन्हें अपने पाठ्यक्रम के पूरा होने पर चुकाना पड़ता है। ऋण लेने वाले अधिकांश छात्र आमतौर पर स्नातक होने के बाद अपने ऋण का भुगतान करने में वर्षों बिताते हैं जिसमें एक निश्चित राशि की ब्याज दर भी शामिल होती है। इससे उनके कंधों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है क्योंकि कर्ज चुकाए जाने तक अपने जीवन में आगे बढ़ने, घर खरीदने और परिवार शुरू करने के बारे में सोचना मुश्किल होता है। यदि छात्र कार्य-अध्ययन कार्यक्रम चुनते हैं, तो वे अपने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान अपने ऋण का भुगतान करने में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकते हैं या अधिकांश समय शैक्षिक ऋण की आवश्यकता भी नहीं होती है। आपके बायोडाटा को अधिक महत्व देता है: आजकल अधिकांश कंपनियां कुछ पूर्व पेशेवर अनुभव वाले कर्मचारियों को प्राथमिकता देती हैं; उस स्थिति में, आपके कॉलेज के समय के दौरान कुछ पूर्व कार्य अनुभव आपका बायोडाटा बनाते हैंवह दूसरों के बीच चमकता है। नियोक्ताओं को अक्सर कॉलेज स्नातकों के बायोडाटा की भरमार का सामना करना पड़ता है और वे हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते हैं जो न केवल ग्रेड के मामले में बल्कि अनुभव के मामले में भी अलग हो। कार्य अनुभव के साथ-साथ अच्छे ग्रेड वाले किसी व्यक्ति के ऐसा करने की संभावना है, खासकर यदि अनुभव प्रासंगिक क्षेत्र में हो। यह प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है, जो नियोक्ता को हमेशा प्रभावित करेगा। अधिकांश बार कुछ पूर्व अनुभवी उम्मीदवारों को कुछ यादृच्छिक नवागंतुकों की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है। बेहतर समय प्रबंधनः अपनी पढ़ाई और अपनी नौकरी के बीच संतुलन बनाने से आपको अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का व्यावहारिक अनुभव मिलता है और जो व्यक्ति दोनों के बीच सफलतापूर्वक संतुलन बनाने में सक्षम होता है वह अच्छे समय प्रबंधन की कला में भी महारत हासिल कर लेता है जो वास्तव में हर पेशेवर के लिए महत्वपूर्ण है। . कॉलेज में पढ़ते समय पढ़ाई करने के नुकसान पढ़ाई से ध्यान भटकानाः हालांकि, कॉलेज में काम करने का एक नकारात्मक पहलू यह है कि छात्रों को इतना अधिक काम करने की क्षमता मिलती है कि उनकी नौकरियां उनके कॉलेज के लक्ष्यों और शैक्षणिक प्रगति में बाधा डालती हैं। आपको अपनी पढ़ाई और नौकरी दोनों के लिए अपना समय देना होगा और कभी-कभी छात्र अच्छी तरह से सामना करने में सक्षम नहीं होते हैं। नौकरी के प्रति प्रतिबद्धता का मतलब यह है कि छात्रों के पास खाली समय कम उपलब्ध है। यदि वे संगठित हों और पढ़ाई के लिए समय निकालने के लिए अपने सामाजिक जीवन में कटौती करें तो यह कोई समस्या नहीं हो सकती है, लेकिन कई छात्र साथियों के दबाव के आगे झुक जाते हैं और इसके बजाय अपने अध्ययन के समय का त्याग कर देते हैं। इसलिए जरूरत बेहतर समय प्रबंधन की है। वास्तव में थका देने वाला हो सकता है: कभी-कभी आपकी दो प्राथमिकताओं के बीच समय का टकराव हो सकता है। यह भी संभव है कि दो प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने से कभी-कभी एक छात्र वास्तव में थक सकता है और संभवतः अपने विषयों को अच्छी तरह से दोहराने के लिए उसके पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी। हर किसी के लिए दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और पढ़ाई के दौरान नौकरी रोकने की कोशिश करना बेहद थका देने वाला हो सकता है, खासकर परीक्षा के समय, जब नियोक्ता उन्हें छुट्टी देने के लिए अनिच्छुक हो सकते हैं। समय के साथ, छात्रों के लिए यह बहुत अधिक हो सकता है और तनाव के कारण वे थक सकते हैं। विकास में बाधाः यह स्पष्ट है कि अधिकांश छात्र अपने जीवन में बाद में उच्च वेतन वाली नौकरी पाने की उम्मीद के साथ कॉलेज आते हैं, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करने की उम्मीद होगी। उस दृष्टिकोण से, कॉलेज के वर्ष दैनिक काम शुरू करने से पहले अध्ययन करने और मौज-मस्ती करने का उनका आखिरी मौका हो सकते हैं, इसलिए कॉलेज में काम करना अनावश्यक रूप से थका देने वाला हो सकता है। कभी-कभी अंशकालिक नौकरी में काम करने से उनका ध्यान बदल सकता है और कुछ छात्र वास्तव में बड़ी तस्वीर पर ध्यान न देते हुए अपनी वर्तमान नौकरी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। काम और पढ़ाई में संतुलन बनाने के टिप्स बहुत सारे छात्र पढ़ाई के साथ-साथ काम का विकल्प भी चुनते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो इसे केवल फुरसत के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए करते हैं। जो छात्र काम करते हैं और अध्ययन करते हैं वे हर चीज़ का सर्वोत्तम आनंद लेते प्रतीत होते हैं। वे अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं और साथ ही अपनी नौकरी बनाए रखने और वेतन पाने में भी सक्षम होते हैं। पढ़ाई के साथ-साथ काम करने के भी अपने फायदे हैं। हालाँकि, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है और काम के साथ-साथ पढ़ाई करना शायद आपके जीवन में सबसे कठिन कामों में से एक है। आपकी सहायता के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं: अच्छा समय प्रबंधन. दो के साथ सही संतुलन बनाएं और एक अच्छी समय-योजना बनाएं। पढ़ाई में जरूरी मदद के लिए स्व-प्रेरणा और दोस्तों से जुड़े रहें। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसके अनुसार काम करें। मौज-मस्ती और मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी समय निकालें। ऐसा न करेंअपनी पढ़ाई को किनारे कर दो. याद रखें पढ़ाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. आप जो करते हैं उसका आनंद लें. अपनी सफलता के लिए स्वयं को पुरस्कृत करें जो आपके लिए प्रेरणा होगी।

विजय गर्ग सेवानिवृत्त प्रिंसिपल

अखबारों और लेखकों की हालत चिंताजनक है

विजय गर्ग

समाचार-पत्रों ने समाज में जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह भूमिका किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है, विश्व के सभी दूरदर्शी देशों में समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता। मीडिया और विशेषकर प्रिंट मीडिया में जनमत को आकार देने की अविश्वसनीय शक्ति है। समाचार पत्र नीति निर्माण में जनता की राय एकत्रित करने और नीति निर्माताओं तक जनता की राय पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करते हैं। भारत में समाचार पत्रों द्वारा पारंपरिक पत्रकारिता की सेवा की जाती है कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। चाहे वह पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र हो, 1779 में जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट हो, या वे समाचार पत्र जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने लगे। सरकारी प्रतिबंध, आर्थिक मंदी और टेलीविजन के विस्तार ने पहले भी समाचार पत्र उद्योग को हिलाकर रख दिया है, लेकिन पहले कभी यह सवाल नहीं पूछ गया कि क्या प्रिंट मीडिया भारत में जीवित रहेगा या नहीं। लेकिन आज अखबारों और लेखकों को भी जीवित रहने के लिए गूगल और फेसबुक को हराना होगा। प्रश्न यह है कि गिरावट कहाँ स्थित हैरास्ता देखते हुए वे ऐसा कैसे करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण कारक समाचार वाहक गूगल, फेसबुक और अन्य का उदय है। एक तरफ वे किसी और द्वारा तैयार की गई खबरें छीन लेते हैं और दूसरी तरफ अखबारों की आजीविका छीन लेते हैं। इससे भी बदतर स्थिति अखबार लिखने वालों की है जो हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब उन्हें भुगतान मिलता है, तो यह समुद्र में मोती खोजने जैसा है, लेकिन लेखक के पास कोई सहारा नहीं होता है। इंटरनेट पर सामग्री की प्रचुरता के कारण समाचार पत्र कहीं से भी उठाया जा सकता हैके लिए छड़ी ऐसे में न तो लेखक की जरूरत होती है और न ही लेखक के सहारे की। इसके कारण आज पत्रकारिता धूर्त लोगों का व्यवसाय बन गई है, जो सैकड़ों प्रतियां छापते हैं या डिजिटल संस्करण लाते हैं। और बदले में विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग लेखकों को साहित्यिक समर्थन देने के बजाय सवाल पूछते हैं। लेखक अपने लेख प्रकाशित करने के लिए पैसे भी मांगते हैं। ऐसी पत्रकारिता शर्मनाक है. यह चिंताजनक स्थिति है क्योंकि समाचार पत्र अपने प्रारूप के कारण आज भी विश्वसनीय हैं, यह तय है। एक अखबार आर पूरा हो गया यह अंततः तैयार है, अपने आप में, निश्चित है। इसके विपरीत, डिजिटल समाचार लगातार अद्यतन, बेहतर और परिवर्तित होते रहते हैं। यह + समाप्ति ही समाचार पत्रों की ताकत है। एक बार कोई चीज छपने के बाद उसे टेलीविज़न या डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह बदला नहीं जा सकता। लेकिन इस जटिल प्रारूप के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक बड़ी दुविधा यह है कि क्या भारतीय पाठक गुणवत्तापूर्ण सामग्री के लिए भुगतान करने में रुचि रखते हैं, जबकि हर जगह मुफ्त सामग्री उपलब्ध है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं है. यदि पाठक भुगतान नहीं करते हैं, नतीजा यह है कि अखबार भी भुगतान के नाम पर अपने लेखकों से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन अगर लेखक ही नहीं बचे तो अखबार खत्म हो जायेंगे। इसलिए लेखकों को जीवित रखना समाचार पत्रों की जिम्मेदारी है। अखबारों के साथ सोचने वाली बात यह है कि लेखकों की आर्थिक स्थिति क्या है? मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कुछ बड़े लेखकों और पत्रकारों को छोड़ दें तो सिर्फ लिखकर अपने परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है। एकमुश्त दो लाख रुपये देखना सपना है. एक साथ इतना पैसा देखकर लेखक अभिभूत क्यों हो जाता है? अखबार की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी नींव हैयह संरचित भी है, जो इसकी समस्या भी है। यह बहुत बड़ा है, क्योंकि बड़ी संपादकीय टीमों, प्रिंटिंग प्रेस, सर्कुलेशन और मार्केटिंग नेटवर्क के कारण उद्योग बड़ी संख्या में मानव श्रम पर निर्भर है। अधिकांश समाचार पत्र अपने राजस्व से उत्पादन लागत पर सब्सिडी देते हैं। सरकार से कोई समर्थन न मिलने के कारण प्रचलन दिन-ब-दिन कम होती जा रही है. लगभग सभी अखबारों की यही कहानी है. वे धन की कमी के कारण बंद हो रहे हैं। समाचार पत्र आज केवल उन लोगों की प्रतिबद्धता के कारण जीवित हैं जो उन्हें चलाते हैं। अखबार हो या गंभीर खबरउद्योग अब समाचार एकत्र करने का केवल एक ही काम नहीं कर सकता। कई प्रारूप। उम्मीद है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, समाचार पत्र इन वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंततः, निजी तौर पर चलाए जाने वाले वीडियो ब्लॉग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ग्रुप और एप्लिकेशन भी समाचार पत्र पोर्टलों से ट्रैफिक छीन रहे हैं, वीडी। उसी स्तर पर, उपभोक्ता समझते हैं कि सोशल मीडिया पर उनके संदेशों का अधिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से दुनिया भर के उपभोक्ता पारंपरिक मीडिया से दूर जा रहे हैं। गंभीर समाचार उद्योग अभी भी उच्च-गुणवत्ता की सामग्री का उत्पादन करके जीवित रह सकता है क्योंकि इसमें अभी भी पुराने समय के ठोस संपादकों की निगरानी में एक मजबूत रिपोर्टिंग टीम है, जो प्रौद्योगिकी से विमुख नहीं हैं और नई पीढ़ी की गतिशीलता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं।

संविधान की दिवस की रस्मी अदायगी से नहीं बदलेगी हकीकत

योगेंद्र योगी

संविधान का दुरुपयोग केंद्र में हर दल की सरकार ने करने की भरसक कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाने का ऐसा मंजर भारत में कभी देखने को नहीं मिला।

26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारत का संविधान व्यावहारिक, लचीला, और मज़बूत है। संविधान में हर समस्या का समाधान है। संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। इसके बावजूद आजादी के बाद से केंद्र हो या राज्यों की सरकारें, सभी ने संविधान में मौजूद कानूनों को अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करने में कसर बाकी नहीं रखी। राजनीतिक दलों की सत्ता लोलुपता के कारण संविधान काफी हद तक कानून का पुलंदा बन कर रह गया। राजनीतिक दलों की मनमानी का आलम ही है कि देश आज भी गरीबी, असमानता, अपराध, जनसंख्या बढ़ोतरी, पर्यावरणीय समस्या और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है।

संविधान का दुरुपयोग केंद्र में हर दल की सरकार ने करने की भरसक कोशिश की है। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए देश में आपातकाल लगा दिया। संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाने का ऐसा मंजर भारत में कभी देखने को नहीं मिला। इसके बाद केंद्र में लंबे अर्से तक शासन में रही कांग्रेस की सरकार ने संविधान के दुरुपयोग में कोई कसर बाकी नहीं रखी। राज्यों की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का जमकर दुरुपयोग किया गया। इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया। श्रीमती गांधी ने विपक्षी और क्षेत्रीय दलों की सरकारों को गिरा दिया। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे नेहरू पसंद नहीं करते थे, उसे गिरा दिया गया। करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें गिरा दी गईं। कुल 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया गया। कांग्रेस सरकार ने डीएमके और वामपंथी सरकारों को गिराया। बदनियति से संविधान के कानूनों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदलने और लागू करने का काम सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, बल्कि केंद्र में शासन में आने के बाद भाजपा भी इसमें पीछे नहीं रही। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99वें संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया और उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया।

देश के लोगों की सोशल मीडिया के जरिए अभिव्यक्ति और असहमति के अधिकार को केंद्र और राज्यों के कुचलने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा ६६ ए को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और गृह सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि सभी लंबित मामलों से धारा ६६ ए का संदर्भ हटा दिया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रकाशित आईटी अधिनियम के बेयरएक्ट्स को पाठकों को पर्याप्त रूप से सूचित करना चाहिए कि धारा 66 ए को अमान्य कर दिया गया है। इस धारा में यह प्रावधान था कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, उत्तेजक या भावनाएं भड़काने वाली सामग्री डालने पर व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 19.1.ए के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताकर निरस्त कर दिया था।

आरक्षण को लेकर सभी राजनीतिक दल वोटों की राजनीतिक करते रहे हैं। आरक्षण के सही प्रावधानों को लागू करने में भी नेताओं को वोटों का डर सताता रहा है। यही वजह रही है कि आरक्षण के फायदे-नुकसान पर कोई दल किसी तरह की चर्चा तक करने को तैयार नहीं होता। आरक्षण को लेकर राजनीतिक दलों ने संविधान से छेड़छाड़ करने में कसर बाकी नहीं रखी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने को मंजूरी दी थी। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से संसद भवन में 100 दलित सांसद मिले। इसके बाद केंद्र ने इसकी घोषणा भी कर दी कि जरूरत पड़ी तो संसद में विधेयक लाया जाएगा, पर आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों में कोई बदलाव मंजूर नहीं होगा। हालांकि तमिलनाडु और कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा के निर्णय पर अमल का फैसला किया।

इतना ही नहीं संविधान से इतर जाकर राज्यों की सरकारों ने भी वोटों की राजनीति के लिए आरक्षण को हथियार बनाने के प्रयासों में कसर बाकी नहीं रखी। हां, कुछ राज्यों ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण देने का कानून बनाने की कोशिश की है। हालांकि, इन कोशिशों को संवैधानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साल 2008 में महाराष्ट्र सरकार ने भूमिपुत्रों को 80 प्रतिशत आरक्षण देने की कोशिश की थी। साल 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण अनिवार्य करने वाला कानून पारित किया था। साल 2020 में हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण देने का कानून बनाया था। हालांकि, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक माना था।

इसी तरह साल 2023 में झारखंड ने निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने वाला कानून पेश किया था। कर्नाटक सरकार ने भी निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण देने का विधेयक पेश किया था। हालांकि, उद्योग जगत की प्रतिक्रिया के बाद इसे स्थगित कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 16(3) के मुताबिक, संसद ही किसी खास राज्य में नौकरियों के लिए निवास की ज़रूरत तय करने का कानून बना सकती है। संविधान दिवस मनाना महज एक रस्मी रिवायत रह गई है। केंद्र के साथ राज्यों के भी कानूनों से खिलवाड़ करने के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया का दबदबा इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक दलों ने कानून को शर्मसार करते हुए अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया है। संविधान के कानूनों का जब तक निष्पक्षता से पालन नहीं किया जाएगा तब तक संविधान दिवस जैसे प्रयास देश की मौजूदा समस्याओं के समक्ष मुंह चिढ़ाने जैसे ही रहेंगे।

दिल्ली सल्तनत पर बार-बार क्यों करते हैं किसान चढ़ाई?

डॉ. रमेश ठाकुर

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं।

अन्नदाताओं की समस्याओं का समाधान आखिर कब होगा? क्या उनकी मांगे भविष्य में कभी पूरी हो भी पाएंगी या नहीं? केंद्र में सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की, हर दौर में यही सब कुछ देखने को मिलता है। कमोबेस, सरकारों का रवैया सदैव एक जैसा ही रहता है। इसलिए एकाएक किसी सरकार को दोषी ठहराना किसी टिप्पणीकार के लिए बेईमानी सा होता है। किसान आंदोलनों से जो समस्याएं उपजती हैं, उसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आमजन ही भुगतते हैं। समस्याएं किस कदर पनपती हैं इस ओर शायद किसी का भी ध्यान नहीं जाता। मरीज, छात्र, राहगीर, दैनिक कर्मी तो बेहाल होते ही हैं, रोजमर्रा के क्रियाकलाप भी रुक जाते हैं। दो दिसंबर को भी यही हुआ, जब किसान उत्तर प्रदेश के एक छोर से चले, तो सड़कों पर दौड़ने वाले तेज वाहनों के पहिए थम गए। क्या मरीज, क्या नौकरीपेशा, सभी के पैर अपने जगह रूक गए।

यह वीनर्स नकली दांतों से 300 गुना बेहतर है! और कीमत बहुत सस्ती है

दरअसल, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करने से उन्हें बलपूर्वक बॉर्डरों पर ही रोका गया है। पर, हालात दिल्ली-एनसीआर के एक बार फिर बिगड़ते दिखाई पड़ने लगे हैं। इस दफे भी किसानों के तेवर उग्र दिख रहे हैं। अन्नदाता लंबा आंदोलन करने के मूड़ में दिखाई पड़ते हैं। इतना तय है, अगर उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते नहीं हुआ, तो हालात पिछले किसान आंदोलन जैसे बनने में वक्त नहीं लगेगा। किसान केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बीते एक महीने से अल्टीमेटम दे रहे थे कि उनकी मांगे मानी जाएं, उनसे बात करे कोई जिम्मेदार व्यक्ति, जिससे दोनों पक्ष बैठकर कोई हल निकाल सकें। लेकिन उनकी बातों को हुकूमती स्तर पर एक बार भी अनसुना और अनदेखा किया गया।

दिल्ली पहुंचने के लिए गौतमबुद्ध नगर से करीब 50,000 से अधिक किसान सोमवार सुबह यानी दो तारीख को नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास एकत्रित हुए, फिर उन्होंने दिल्ली कूच का प्लान किया, हालांकि तत्काल रूप से तो पुलिस ने उनकी योजना को विफल कर दिया है। लेकिन किसान बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं, वह किसी भी सूरत में दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। उनको लगता है संसद का शीत सत्र चालू है। पूरी हुकूमती मशीनरी इस समय एक साथ है, उनकी बातें आसानी से पहुंच सकती है। पर, ऐसा होता दिख नहीं रहा। केंद्र सरकार इतनी आसानी से सबकुछ मान लेगी, ऐसा भी दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए किसान भी काफी उग्र हैं। अपने साथ लंबे आंदोलन को करने के लिए तामझाम लेकर पहुंच हैं। राशन, टैक्टर, मोटरसाइकिल, गैस सिलेंडर, तंबू आदि है उनके पास।

किसानों ने दिल्ली मार्च का प्लान अचानक से ही बनाया। पहले की प्री-प्लान नहीं थी। क्योंकि किसान अपनी विभिन्न मांगो को लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण पर पिछले कुछ दिनों से धरनागत थे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, उन्हें ज़मीन के बदले 10 पर्सेंट निर्मित प्लॉट और 64 पर्सेंट बढ़ा हुआ जमीन का शेष मुआवज़ा दिया जाए। साथ ही जितने किसान जमीन छिन जाने से भूमिहीन हुए हैं, उनके परिवार के बच्चों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई न कोई रोजगार जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं, इसके अलावा एमएसपी गारंटी कानून लागू करें। फसलों की कीमतें डबर हों, खाद, बीज व कीटनाशक दवाईयों के रेट कम किए जाएं जैसी पुरानी मांगे भी उनकी बरकरार हैं। इस वक्त मंडियों में धान की खरीद में जो घटतौली हो रही है उसे तुरंत रोका जाए। ये मांगे ऐसी जिसे शायद ही सरकारें मांगे।

प्रतीत ऐसा होता है कि ये किसान मूवमेंट भी बडा रूप ले सकता है। अभी तक गनीमत ये समझी जाए, इस मोर्चे में सिर्फ दर्जन भर ही किसान संगठन शामिल हुए हैं। हालांकि बाहर से करीब सौ से ज्यादा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है। मोर्चे को रोकने को अगर कोई जल्द विकल्प नहीं निकाला गया, तो अन्य किसान संगठन भी कूदने में देर नहीं करेंगे। हांलाकि सोमवार को किसान मोर्चे को देखते हुए नोएडा ट्रैफ़कि पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी की गई जिसमें कालिंदी कुंज बॉर्डर, यमुना एक्सप्रेस-वे और डीएनडी बॉर्डर से बचने की लोगों को सलाह दी गई, क्योंकि इन जगहों पर मोर्चे का असर व्यापक रूप से देखने को मिला। लोग अनचाई परेशानी से जूझते दिखाई पड़े, स्कूली बच्चों भी जाम में फंसे रहे, एमबूलेंस भी नहीं निकल पाईं। नौकरीपेशा समय से अपने कार्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ये हालात ऐसे ही बने रहेंगे, जब तक ये मूवमेंट चलता रहेगा।

किसान मूवमेंट शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही राजनीति भी आरंभ हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने कहा दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग, वाटर कैनन, दंगा नियंत्रण गाड़ियां और अमित शाह की पूरी पुलिस तैनात की गई। ऐसा प्रतीत होता है जैसे की उनको किसी आंतकवादी को रोकना या पकड़ना हो? किसान भूमि अधिग्रहण का उचित मुआवज़ा और फसल के सही दाम की मांग लेकर दिल्ली आकर सोती सरकार को जगाना चाहते हैं इसमें बुरा क्या है? वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से बयान आया जिसमें कहा गया कि राष्ट्र की राजधानी किसी की बपौती तो है नहीं? फिर किसान क्यों नहीं आ सकते? प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने हमला किया। बोले, किसानों पर बर्बरता के नए आयाम रच रहे हैं प्रधानमंत्री। उनके दिल में अन्नदाताओं के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि किसान अपनी जायज मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं, उन्हें आने देना चाहिए, उनपर वाटर कैनन का प्रयोग करना गलत है। दरअसल, ऐसे मौकों पर विपक्ष का बिना सोचे समझे कूद पड़ना, 'आग में घी डालने' का काम कर जाता है। जबकि, उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर विकल्प और समाधान की ओर ध्यानाकर्षण करवाना चाहिए। ताकि सरकार आंदोलनकारियों से बात करने पर विवश हो? पर, दुर्भाग्य ऐसा हो नहीं पाता और न ही विपक्ष ऐसा प्रयास करता है।

- डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), भारत सरकार!

QR Pan Card पाना आसान, इनटैक्स वेबसाइट पर जाकर फॉलो करें ये स्टेप

परिवहन विशेष न्यूज

नवंबर के महीने में सरकार ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट (Pan 2.0 Project) का एलान किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अब यूजर आसानी से ई-पैन पा सकते हैं। यह पैन-कार्ड में क्यूआर कोड होगा जो इसे पुराने कार्ड से अलग बनाएगा। हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि आप न्यू पैन कार्ड के लिए कहां जाकर अप्लाई करें।

पैन कार्ड पाना बहुत आसान

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत सरकार ने नवंबर महीने के अंत में PAN 2.0 प्रोजेक्ट (Pan 2.0 Project) लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट में सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत नया पैन कार्ड (Pan Card) लॉन्च किया था। नए पैन कार्ड में QR कोड होगा। इस कार्ड को पुराने कार्ड से ज्यादा सेफ और सिक्योर बनाया गया है।

अगर आप भी यह कार्ड पाना चाहते हैं तो बता दें कि इसके लिए आवेदन करने का तरीका काफी आसान है। आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई?

स्टेप 1: आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के वेबसाइट (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर जाना है।

स्टेप 2: अब आप ई-पैन के ऑप्शन को सेलेक्ट करें।

स्टेप 3: इसके बाद आपको Apply for Instant PAN को सेलेक्ट करना है।

स्टेप 4: अब आपको अपना 12 डिजिट का आधर नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 5: आधार नंबर दर्ज करने के बाद लिंक्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को भरें।

स्टेप 6: अब सही ई-मेल आईडी और बाकी सभी जानकारी भरें और सबमिट करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद करीब 30 मिनट में आपके ई-मेल आईडी पर ई-पैन (e-PAN) आ जाएगा। आप इसे पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें: Fixed Vs Floating: फटाफाट खत्म हो जाए Loan, स्विच का ऑप्शन अपनाएं और कम ब्याज में खत्म करें लोन

पैन 2.0 क्या है? (What is Pan 2.0?)

पैन 2.0 भी एक तरह का पैन कार्ड है। यह पैन कार्ड डिजिटल है यानी यह पेपरलेस कार्ड है। इस कार्ड में क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड के माध्यम से पैन होल्डर की जानकारी पाई जा सकती है। इस कार्ड में सभी जानकारी पूरी तरह से एनक्रिप्टेड होगी। सरकार फिजिकल कार्ड का इस्तेमाल कम करना चाहती है, इस वजह से पैन 2.0 को लॉन्च किया गया है।

यह कार्ड पुराने कार्ड से ज्यादा सिक्योर भी है। इसके अलावा इस कार्ड के लिए आपको 15 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आवेदन के करीब 30 मिनट में आपके मेल-आईडी पर पैन कार्ड आ जाएगा। आपको बता दें कि इस कार्ड के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।

पूरे सप्ताह रहेगा आईपीओ का भरमार, 11 कंपनियां जुटाएंगी 18,500 करोड़ रुपये

परिवहन विशेष न्यूज

इस हफ्ते पांच मेनबोर्ड आईपीओ के साथ छह एसएमई के आईपीओ आने वाले हैं। आपको बता दें कि इस साल में अब तक 78 मुख्य बोर्ड की कंपनियों का आईपीओ आ गया है। इन आईपीओ ने लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस सप्ताह भी 11 आईपीओ करीब 18500 करोड़ रुपये जुटा सकती है। पढ़ें पूरी खबर

पीटीआई, नई दिल्ली। इस सप्ताह विशाल मेगा मार्ट, टीपीजी कैपिटल समर्थित साई लाइफ साइंसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स जैसी 11 कंपनियां आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने को तैयार हैं। इन सभी कंपनियों का सामूहिक तौर पर लगभग 18,500 करोड़ रुपये जुटाना लक्ष्य है।

इस दौरान पेश किए जाने वाले मुख्य बोर्ड के अन्य आईपीओ में इन्वेंटुरस नालेज साल्यूशंस लिमिटेड और ब्लैकस्टोन के स्वामित्व वाली डायमंड ग्रेडिंग कंपनी इंटरनेशनल जेमोलाजिकल इंस्टीट्यूट (इंडिया) लिमिटेड शामिल हैं। पांच मेनबोर्ड आईपीओ के साथ छह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एसएमई) अगले सप्ताह अपने पहले सार्वजनिक निर्गम जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। इनका लक्ष्य सामूहिक रूप से 150 करोड़ रुपये से अधिक जुटाने का है। कंपनियां मौजूदा शेयरधारकों को बाहर निकलने का रास्ता उपलब्ध कराने, विस्तार योजनाओं के लिए धन जुटाने, कर्ज चुकाने और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिक बाजार का इस्तेमाल कर रही हैं।

साल 2024 में अब तक हुंडई मोटर इंडिया, स्विगी, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी 78 मुख्य बोर्ड की कंपनियों ने सामूहिक रूप से लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह 2023 में इस मार्ग से 57 कंपनियों द्वारा जुटाए गए 49,436 करोड़ रुपये से कहीं अधिक है।

विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबिक्विक के आइपीओ 11 दिसंबर को

दिसंबर के पहले हफ्ते में कैसी रहेगी बाजार की चाल, कौन-से फैक्टर्स रहेंगे अहम

शेयर बाजार के लिए यह हफ्ता काफी उतार-चढ़ाव रहने वाला है। इस हफ्ते कई फैक्टर्स बाजार की चाल को तय करेंगे। मार्केट एनलिस्ट ने बताया कि आरबीआई की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक के फैसलों का असर शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि शेयर बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स अहम रहने वाल है।

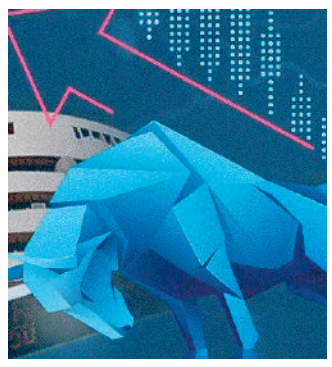

नई दिल्ली। कल से दिसंबर का पहला कारोबारी हफ्ता शुरू हो जाएगा। यह हफ्ता शेयर बाजार के लिए काफी अहम रहने वाला हैं। शुक्रवार को जारी हुए दूसरी तिमाही के जीडीपी ग्रोथ आंकड़ों का असर सोमवार को शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। ऐसे में मार्केट एनलिस्ट ने बताया है कि इस हफ्ते शेयर बाजार के लिए कौन-से फैक्टर्स अहम रहने वाले हैं।

मार्केट एनलिस्ट के अनुसार इस हफ्ते ग्लोबल ट्रेंड, फॉरेन फंड मूवमेंट के साथ आरबीआई द्वारा जारी रेपो रेट (Repo Rate) के फैसलों का असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। इसके अलावा ऑटो सेल्स डेटा का असर ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है।

ये फैक्टर्स रहेंगे अहम

चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 फीसदी रही। यह अनुमान से काफी कम है। जीडीपी ग्रोथ में इस गिरावट का असर सोमवार को देखने को मिल सकता है। हालांकि, इस हफ्ते होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक (RBI MPC MEET 2024) में रेपो रेट के साथ कई अहम फैसले लिए जाएंगे। इन फैसलों का सीधा असर स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकता है। यह वह फैक्टर्स है जिनपर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये शेयर बाजार की चाल को प्रभावित करेंगी।

भू-राजनीतिक टेंशन खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण ग्लोबल मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते पीएमआई सर्विस और मैन्यूफैक्चरिंग डेटा जारी होंगे। इसके अलावा यूएस जॉब डेटा भी बाजार के सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकते हैं।

जीडीपी की धीमी रफ्तार

भारत की अर्थव्यवस्था काफी धीमी गति से बढ़ रही है। यह पिछले दो साल में सबसे निचले स्तर पर हैं। मैन्यूफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर की अच्छी परफॉर्मेंस न होने के कारण जीडीपी ग्रोथ दूसरी तिमाही में काफी धीमी रही। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 5.4 फीसदी रही, जबकि 6.5 फीसदी का अनुमान था।

पिछले सप्ताह शेयर बाजार के दोनों स्टॉक एक्सचेंज पॉजिटिव नोट पर बंद हुई थी। हालांकि, इस हफ्ते शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड का उतार-चढ़ाव और रुपये-डॉलर का रुख भी शेयर बाजार के रुझान को तय करेगा।

वित्तीय संकट से गुजर रहे लोग? गिरवी रख रहे सोना, सात महीनों में 50 फीसदी बढ़ गया गोल्ड लोन

परिवहन विशेष न्यूज

आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में बैंकों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले ऋण में 50.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह तेज वृद्धि तब हुई है जब हर दूसरे पर्सनल लोन सेगमेंट में क्रेडिट सिंगल डिजिट में बढ़ा है।आरबीआई ने कहा कि पहले सात महीनों में गोल्ड लोन में बढ़ोतरी के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं।

नई दिल्ली। हमारे देश में अपना कीमती सामान गिरवी रखना पुरानी कवायद रही है। लेकिन अगर कोई सोना गिरवी रख रहा है तो समझलो वह वित्तीय संकट से गुजर रहा है। हालांकि यह सिर्फ एक अंदाजा है। आरबीआई के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में बैंकों द्वारा सोने के आभूषणों के बदले ऋण में 50.4 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह तेज वृद्धि तब हुई है, जब हर दूसरे पर्सनल लोन सेगमेंट में क्रेडिट सिंगल डिजिट में बढ़ा है।

पर्सनल लोन भी बढ़ा

आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी बैंक क्रेडिट के सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि 18 अक्टूबर, 2024 तक 1,54,282 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन बकाया था। मार्च 2024 के अंत में, कुल गोल्ड लोन बकाया 1,02,562 करोड़ रुपये था। अक्टूबर 2023 में 13% की तुलना में साल-दर-साल वृद्धि 56% थी।

गोल्ड लोन में बढ़ोतरी के लिए कई कारक जिम्मेदार

आगे आरबीआई ने कहा कि पहले सात महीनों में गोल्ड लोन में बढ़ोतरी के लिए कई कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, जिनमें एनबीएफसी से बदलाव और असुरक्षित ऋण की तुलना में सुरक्षित ऋण को प्राथमिकता देना शामिल है। साल के पहले सात महीनों के दौरान एनबीएफसी को दिया जाने वाला बैंक ऋण 0.7% घटकर 1.5 लाख करोड़ रुपये रह गया है।

सोने के ऋण में वृद्धि इसकी कीमतों में वृद्धि

बैंकरों ने यह भी कहा कि सोने के ऋण में वृद्धि इसकी कीमतों में वृद्धि के कारण हो सकती है, जो उधारकर्ताओं को पुराने ऋण चुकाने और अधिक नए ऋण सुरक्षित करने का अवसर प्रदान करती है। कुछ विश्लेषक गोल्ड लोन की बढ़ती मांग को वित्तीय संकट के संकेत के रूप में देखते हैं।

पर्सनल लोन सेगमेंट में, होम लोन में साल-दर-साल हो रही वृद्धि

पिछले महीने आरबीआई ने बैंकों और वित्त कंपनियों को अपनी गोल्ड लोन नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने का निर्देश देते हुए उन्हें तीन महीने के भीतर किसी भी कमी को दूर करने का निर्देश दिया था। पर्सनल लोन सेगमेंट में, होम लोन में साल-दर-साल वृद्धि 5.6% थी।

बैंकों का होम लोन 28.7 लाख करोड़

बैंकों का होम लोन बुक बढ़कर 28.7 लाख करोड़ रुपये हो गया। अक्टूबर 2023 में 36.6% की तुलना में होम लोन में साल-दर-साल वृद्धि 12.1% थी। अगली उच्चतम वृद्धि क्रेडिट कार्ड बकाया में थी, जो सात महीनों में 9.2% बढ़कर 2.81 लाख करोड़ रुपये हो गई।

जॉब चेंज के साथ क्या UAN भी बदल जाता है, क्या कहता है ईपीएफओ का नियम

परिवहन विशेष न्यूज

EPFO Rule आपक बता दें कि अभी ईपीएफओ द्वारा एक्टिव यूएएन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि वह अपने यूएएन को एक्टिव रखें। हमारे मन में एक सवाल बना रहता है कि जॉब चेंज करने के बाद क्या यूएएन नंबर भी बदल जाता है। आइए इस आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।

नई दिल्ली। ईपीएफओ (EPFO) हर मुमकिन कोशिश करता है कि वह अपने सदस्यों का अच्छे से अच्छी सर्विस दे। इसके लिए ईपीएफओ जल्द ही 3.0 (EPFO 3.0) प्रोजेक्ट ला सकता है। हालांकि, अभी तक इसको लेकर कोई अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

ईपीएफओ को लेकर कई लोगों के मन में एक सवाल बना रहता है कि जब भी जॉब चेंज होती है तो फिर ईपीएफओ में निवेश के लिए न्यू यूएएन नंबर (UAN Number) जनरेट करना पड़ता है। इसको लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूजन बनी रहती है। हम आपको नीचे इस सवाल का जवाब देंगे। इसका जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर यूएएन नंबर क्या है?

यूएएन नंबर क्या है? (What is UAN Number?)

यूएएन नंबर एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जो ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। यह नबंर 12 डिजिट का होता है। हर ईपीएफओ के पास यूनिक यूएएन नंबर होता है। यह एक तरह से बैंक अकाउंट नंबर की तरह काम करता है। इस नंबर के जरिये ईपीएफओ फंड से निकासी और ईपीएफओ अकाउंट को ट्रांसफर करने में मदद मिलती है।

क्या बदलना पड़ता है यूएएन नंबर

ईपीएफओ ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स (X) पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट के अनुसार अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको यूएएन नंबर चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। दरअसल, एक ईपीएफ अकाउंट पर एक ही यूएएन नंबर जारी होता है। अगर किसी मेंबर के पास दो ईपीएफओ अकाउंट होता है तो उन्हें उसे इन अकाउंट को मर्ज करवाना होता है। दरअसल, ईपीएफओ के नियमों के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के पास केवल एक ही पीएफ अकाउंट होना चाहिए।

अगर किसी के पास दो यूएएन नंबर होता है तो उसे ईपीएफओ पोर्टल पर जाकर पिछले यूएएन सर्विस को वर्तमान यूएएन में ट्रांसफर करवाना होगा।

एक्टिव रखें यूएएन नंबर

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अनुसार सभी कर्मचारियों को अपना यूएएन नंबर एक्टिव रखना होगा। अगर यूएएन नंबर एक्टिव नहीं रहता है तो ईपीएफओ मेंबर को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, ईपीएफओ ने यूएएन नंबर एक्टिव रखने की डेडलाइन 30 नवंबर 2024 दी थी, जो अब बीत चुकी है। अगर आपने भी अभी तक अपना यूएएन नंबर एक्टिव नहीं किया है तो आपको एक बार नियोक्ता या फिर ईपीएफओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए।

विदेशी निवेशकों ने अपनाई निकासी की रणनीति, नवंबर में बेचे 22,420 करोड़ रुपये की इक्विटी

नई दिल्ली। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के एलान के बाद विदेशी निवेशक (FPI) भारतीय शेयर बाजार से निकासी कर रहे थे। इस निकासी के कारण शेयर बाजार (Share Market) में भारी बिकवाली देखने को मिली। अब नवंबर महीने में एफपीआई आउटफ्लो का डेटा जारी हो गया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये तक की इक्विटी बेची। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निकासी करके चीन में निवेश कर रहे हैं। यूएस डॉलर (US Dollar) के मजबूत होने के कारण भी विदेशी निवेशक निकासी कर रहे हैं। नवंबर में हुए आउटफ्लो के बाद एफपीआई (FPI Data November 2024) ने 2024 में कुल 15,827 करोड़ रुपये की निकासी की है।

भारत में फोरविस मजार्स के वित्तीय सलाहकार भागीदार अखिल पुरी के अनुसार शेयर बाजार में एफपीआई इनफ्लो थोड़े समय के बाद चालू हो सकती है। जनवरी से पहले एफपीआई इनफ्लो जारी होने की उम्मीद है। अभी एफपीआई आउटफ्लो ने बाजार की चाल को सीमित कर दिया है।

अभी तक कितनी हुई निकासी

एफपीआई डेटा के अनुसार नवंबर में अभी तक विदेशी निवेशकों ने 22,420 करोड़ रुपये की निकासी की है। पिछले महीने में अक्टूबर में 94,017 करोड़ रुपये की निकासी की थी। यह इस साल का अभी तक सबसे ज्यादा आउटफ्लो है। अक्टूबर 2024 से पहले विदेशी निवेशकों ने मार्च 2020 में सबसे ज्यादा निकासी की थी। मार्च 2020 में एफपीआई ने 61,973 करोड़ रुपये विड्रॉल किया है। सितंबर 2024 में विदेशी निवेशकों ने 57,724 करोड़ रुपये का इनफ्लो किया था, जो 9-महीने का उच्चतम स्तर है।

एफपीआई ने क्यों अपनाई आउटफ्लो रणनीति

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार के अनुसार एफपीआई ने अक्टूबर से निकासी की रणनीति तीन कारण की वजह से अपनाई है। यह तीन वजह- भारत में उच्च वैल्यूएशन, निराशाजनक तिमाही नतीजे और ट्रंप ट्रेड है।

एफपीआई ने इस समीक्षाधीन अवधि के दौरान डेट मार्केट में 42 करोड़ रुपये और वीआरआर में 362 करोड़ रुपये का निवेश किया। इस साल अब तक एफपीआई ने डेट मार्केट में 1.06 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है।

पिछले सप्ताह 8 कंपनियों का बढ़ा एम-कैप, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस रहा टॉप गेनर

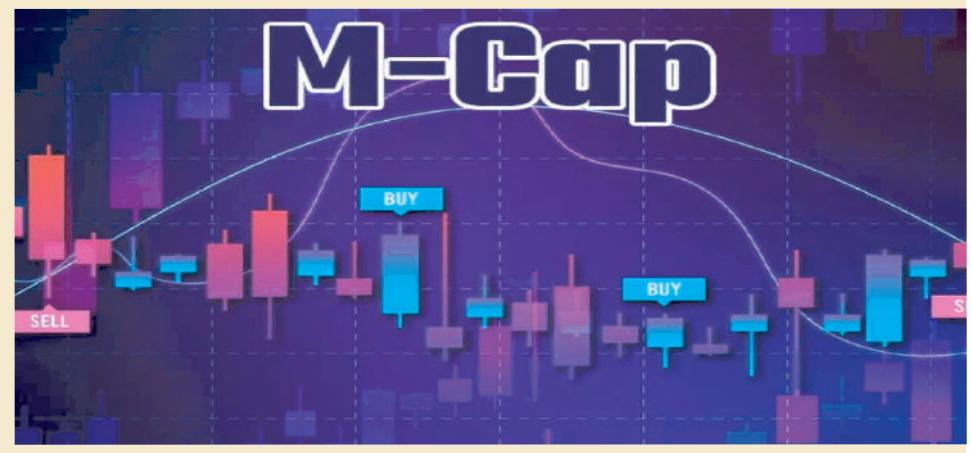

शेयर बाजार में पिछले हफ्ते शानदार तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक 2.5 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए थे। शेयर बाजार में आई इस तेजी के बाद टॉप-10 वैल्यूएशन कंपनी में से 8 के एम-कैप में तेजी आई है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार की टॉप-10 फर्म में से 8 कंपनियों का एम-कैप पिछले हफ्ते बढ़ा है। इन 8 कंपनियों के एम-कैप में संयुक्त रूप से 1,55,603.45 करोड़ रुपये की बढ़त हुई है। बाजार के टॉप गेनर एचडीएफसी बैंक और टीसीएस रहे। हालांकि, एलआईसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप लूजर रहे।

इन फर्म के एम-कैप में आई तेजी

● एचडीएफसी बैंक एम-कैप सबसे ज्यादा बढ़ा है। पिछले सप्ताह कंपनी का बाजार मूल्यांकन 40,392.91 करोड़ रुपये बढ़कर 13,34,418.14 करोड़ रुपये हो गया।

● टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का एम-कैप 36,036.15 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,36,149.51 करोड़ रुपये हो गया।

● आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 16,266.54 करोड़ रुपये बढ़कर 9,01,866.22 करोड़ रुपये हो गया।

● इन्फोसिस का बाजार पूंजीकरण 16,189.33 करोड़ रुपये बढ़कर 7,90,151.83 करोड़ रुपये हो गया है।

● हिंदुस्तान यूनिलीवर का एमकैप 13,239.95 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 5,74,569.05 करोड़ रुपये हो गया।

● आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 11,508.91 करोड़ रुपये बढ़कर 5,94,272.93 करोड़ रुपये हो गया।

● भारती एयरटेल का एमकैप 11,260.11 करोड़ रुपये बढ़कर 8,94,068.84 करोड़ रुपये हो गया।

● भारतीय स्टेट बैंक का बाजार मूल्यांकन 10,709.55 करोड़ रुपये बढ़कर 7,28,293.62 करोड़ रुपये हो गया।

पिछले सप्ताह केवल एलआईसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के एम-कैप में गिरावट आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम-कैप 2,368.16 करोड़ रुपये घटकर 17,13,130.75 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, एलआईसी का बाजार पूंजीकरण 11,954.24 करोड़ रुपये घटकर 5,62,545.30 करोड़ रुपये रह गया है।

क्या है टॉप-10 फर्म की रैंकिंग

एम-कैप में आई गिरावट के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाजार की टॉप फर्म है। इसके बाद टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, भारतीय स्टेट बैंक, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी आते हैं।

भारतरत्न डॉ. बाबा साहेब की पुण्य तिथि पर राजेश खुराना के प्रतिष्ठान पर उन्हें नमन कर अर्पित की श्रद्धांजलि

पूज्य डॉ. बाबा साहेब कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं : राजेश खुराना
आज के युवा जमकर पूज्य डॉ. बाबा साहेब के विचारों को पढ़ते हैं और साझा करते हैं : राजेश खुराना

आगरा,संजय साग़र सिंह। भारतीय संविधान के जनक के पूज्य भारतरत्न डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। हर साल पूज्य बाबा साहेब की पुण्य तिथि के इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महापरिनिर्वाण दिवस पर आगरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के सदस्य राजेश खुराना के प्रतिष्ठान पर डॉ. बाबा साहेब को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

संविधान शिल्पी, भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस (पुण्य तिथि) पर उन्हें कोटि-कोटि नमन करते हुए आगरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के सदस्य राजेश खुराना ने कहा, ₹डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि पूज्य डॉ बाबासाहेब कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं। आज के युवा जमकर उनके विचारों को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। पूज्य डॉ. बाबा साहेब भारतीय संविधान के शिल्पकार होने के साथ-साथ सामाजिक समरसता के अमर पुरोधा थे, जिन्होंने शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें मेरा सादर नमन, उनका संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और समान अधिकार मिलने चाहिए, और इसके लिए हमें लगातार संघर्ष करना होगा। आज, उनके योगदान को याद करना और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाना हमारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि हम समाज में समानता, न्याय और भाईचारे की भावना को मजबूत कर सकें। पूज्य डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जी भारत के संविधान निर्माता हैं। उनकी अध्यक्षता में ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया गया था। उन्होंने जीवनभर जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत और असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और

लोगों को जागरूक किया।"

श्री खुराना ने आगे कहा, ₹डॉ. बाबा साहेब कभी हार ना मानने का हौसला देते हैं। उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके महत्वपूर्ण विचार और राष्ट्रवादी चिंतन एवं कथन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज के युवा जमकर उनके विचारों को पढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। उनके योगदान और उनके विचार आज के युवा समाज को जागरूक करने का एक सशक्त मंत्र बन चुका है। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है, जो समाज में बदलाव ला सकता है, और इसी कारण उन्होंने शिक्षा की महत्ता को हमेशा प्राथमिकता दी।"

अंत में, उन्होंने कहा, ₹वे समाज में समानता की आवश्यकता पर बल देते थे, और यही कारण था कि उन्होंने भारतीय समाज में जातिवाद और अशिक्षा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने महिलाओं के उत्थान की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए, यह सोचते हुए कि एक समाज की प्रगति को उस समाज में महिलाओं की स्थिति से मापा जाना चाहिए। उनका यह विचार आज भी सामाजिक सुधारक और कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक है। डॉ. अंबेडकर जी चाहते थे कि समाज में व्याप्त धार्मिक और सामाजिक असमानताओं का अंत हो। उनके जीवन और विचारों से यह स्पष्ट है कि समाज सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है।"

भुवनेश्वर में सीबीआई का छापा: 100 करोड़ रुपये की डील

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : पश्चिम बंगाल में एक निर्माण परियोजना में हेरफेर के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम भुवनेश्वर पहुंची है। शनिवार की रात स्थानीय मे फेयर होटल के सामने वाली गली में सीबीआई की टीम ने छापेमारी कर एक महंगे काले रंग के व्हील से 20 लाख रुपये से अधिक की रकम बरामद की। साथ ही पुलिस की मदद से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।हिरासत में लिए गए लोगों में से एक ओडिशा का बिल्डर है जबकि दूसरा सेवानिवृत्त केंद्रीय अधिकारी है। हालांकि कल से चल रही इस बड़ी छापेमारी में सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों को भी पकड़ लिया है। इसके अलावा सीबीआई ने एक और सफेद कार जब्त की है।

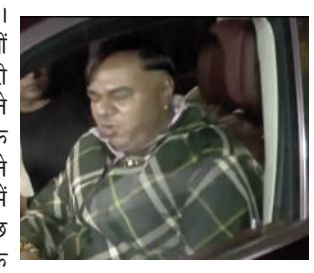

अधिकारी ने सड़क पर तीन लेन बदलीं और मई मेले में पहुंचे। डील में सरकारी अधिकारी को सीबीआई की टीम ने पकड़ा सरकार बाबू ब्रिज एंड रूफ कंपनी के संपर्क में थे। सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों को हिरासत में लिया है और उनसे आगे की पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीबीआई टीम ने शनिवार रात करीब 9:10 बजे होटल के सामने सड़क पर ओडी-05-9999 नंबर की मर्सिडीज कार में सवार चार लोगों को पकड़ा। लेन की जांच की तो एक बैग से 20 लाख से ज्यादा पैसे निकले। इसी बीच कार में बैठे शख्स से सीबीआई अधिकारी की बहस हो गई। सीबीआई टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचित करने के बाद, नेपल्स और मैत्री बिहार पुलिस पश्चिम बंगाल पहुंची और उक्त मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया और कार में सवार लोगों को थाने ले गई। वहां से सीबीआई के अधिकारी उन्हें दूसरी जगहों पर ले जाकर पूछताछ कर रहे हैं।विशेष सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार ओडिशा का बिल्डर पश्चिम बंगाल में कंस्ट्रक्शन का काम लेकर आया था। उस काम में हेराफेरी के 15 दिन से भी कम समय में सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई गई। उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह सीबीआई की छापेमारी जारी रही।

स्वाद उत्तपम, कविता अनुपम!

जो आपने स्वाद लिया है उत्तपम,
मैं भी कविता गढ़ता रहा अनुपम।
हा,आपका रहा खाने में पूरा ध्यान,
अच्छा रहा नहीं था कोई व्यवधान!
गजब का पहना था आपने परिधान।

जो आपने स्वाद लिया है उत्तपम,
मैं भी कविता गढ़ता रहा अनुपम।
सच, क्या करूं तारीफ खाने की,
कहीं जाने और साथ निभाने की!
तेरी अदा प्यारी है मुझे मनाने की।

जो आपने स्वाद लिया है उत्तपम,
मैं भी कविता गढ़ता रहा अनुपम।
पूछ ही लिया और कुछ खाना है,
बंदा पानी-पूरी का नहीं दीवाना है!
तुझे खिलाकर, मुझे मजा आना है।

जो आपने स्वाद लिया है उत्तपम,
मैं भी कविता गढ़ता रहा अनुपम।
क्या? लिखू तू खुद एक कविता है,
तेरी बर्तनवाली का नाम सविता है!
धनंजय तेरे ख्वाबों में ही जीता है।

संजय एम तराणेकर

कमजोर वर्गों के बदलाव, सशक्तिकरण और नई सोच की कहानी लिखते डॉ.मोहन यादव

(डॉ हितेश वाजपेयी -विनायक फीचर्स)

मध्य प्रदेश, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के लिए जाना जाता है, अब कमजोर वर्गों के कल्याण में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। डॉ. मोहन यादव के एक वर्ष के सफल कार्यकाल में अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए न केवल बड़े कदम उठाए गए, बल्कि योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू किया गया। यह कहानी केवल आंकड़ों की नहीं है, यह बदलाव, सशक्तिकरण, और एक नई सोच की कहानी है।

जनजातीय वर्ग: सपनों को पंख देने का अभियान
तेंदूपत्ता संग्राहकों की मुस्कान

जहां पहले तेंदूपत्ता संग्राहकों को 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा मिलता था, अब मोहन सरकार ने यह राशि 4,000 रुपये कर दी है। इससे 30 लाख से अधिक संग्राहकों के चेहरों पर खुशी की चमक आई है। साथ ही,115 करोड़ रुपये का बोनस देकर सरकार ने यह साबित किया है कि मेहनतकश हाथों को उनका हक देना प्राथमिकता है।

आदिवासी बहनों के लिए 'आहार अनुदान योजना'

मोहन-सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति की 2.18 लाख बहनों को 450 करोड़ रुपये की सहायता राशि देकर उनके जीवन में पोषण और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिख दिया है।

शिक्षा: भविष्य को रोशन करने की पहल

"पढ़ाई में आगे, हर चुनौती को पीछे" – इस सोच के साथ जनजातीय विद्यार्थियों को आकांक्षा योजना के तहत जेईई, क्लैट, और नीट की तैयारी का मौका दिया गया। इसके साथ ही मोहन-सरकार ने 728 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जिसने बच्चों के सपनों को नए पंख दिए।

इतिहास और संस्कृति का सम्मान

मोहन-सरकार ने छिंदवाड़ा में श्री बादल भोई संग्रहालय और जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह संग्रहालय का लोकार्पण कर आदिवासी योद्धाओं की गाथाओं को अमर कर दिया।

अनुसूचित जाति: नए अवसरों की दस्तक
बजट बढ़ा, उम्मीदें भी बढ़ीं

अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए मोहन-सरकार ने 27,900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। यह केवल एक संख्या नहीं है, यह उन हजारों परिवारों के सपनों को साकार करने की उम्मीद है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं।

छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी: पढ़ाई का हर सपना अब संभव

घुमंतू और विमुक्त वर्ग के बच्चों के लिए मोहन-सरकार ने छात्रवृत्ति 1,230 रुपये से बढ़ाकर 1,550 रुपये (लड़कों के लिए) और 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,590 रुपये (लड़कियों के लिए) कर दी है। अब हर बच्चा अपनी किताबें, यूनिफॉर्म और पढ़ाई का खर्च आसानी से उठा सकता है।

हेल्पलाइन: हर समस्या का समाधान

छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 24x7 मित्र हेल्पलाइन ने यह सुनिश्चित किया है कि उनका मार्गदर्शन कभी रुक न पाए।

कानपुर में बोले सीएम आदित्यनाथ :(जो अच्छा लगता हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो

सुनील बाजपेई

कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश और समाज के हित में जो उचित लगता हो उसका अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए।

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

रामा विश्वविद्यालय, मंधना के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।

ऋषि मुनियों और धार्मिक ग्रंथो का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा- भारतीय दृष्टि देखिए कितनी महान थी। हमने सत्य के मार्ग पर चलने की बात कही है। यानी सत्य के साथ-साथ धर्म के मार्ग का अनुसरण करो।

उन्होंने कहा- अगर दुनिया के अंदर धर्मों को किसी ने समझा है तो भारतीय ऋषियों ने समझा है। उपासना तक सीमित नहीं रखा। किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। आपकी मर्जी आप मेरी बात मानो या न मानो। देश और समाज के लिए जो अच्छा लगता हो उसका आचरण करके आगे बढ़ो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे यह भी कहा कि कोई भी भारत का सनातन धर्मावलंबी

ये नहीं कह सकता है कि वह तभी हिन्दू है जब वह मंदिर जाएगा। जो जाएगा वह भी है और जो नहीं जाएगा वह भी है। कोई बाध्यता नहीं है उसके लिए। मैं वेदों को मानू न शानू, मैं शास्त्रों में विश्वास करूं न करूं। तभी मेरा हिन्दुज्म कही मुझसे भाग नहीं जा रहा है। वह तब भी हमें जोड़कर चल रहा है।

उपासना विधि की भी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म को हमने कभी उपासना विधि तक सीमित नहीं किया। किसी एक ईष्ट या एक ग्रंथ तक सीमित नहीं किया। उन्होंने कहा-आज भी हर एक भारतीय परिवार अपने घर में वैदिक ग्रंथ संजो कर रखता है। उसे पता है कि यह मेरी पहचान है।

उन्होंने धर्म को बहुत सूक्ष्म तत्व बताते हुए कहा कि उसे हर कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए जो भी हमारे महापुरुष कहें उनके मार्ग का अनुसरण करो।

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट की भी चर्चा की और कहा कि डिजिटल अरेस्ट की बहुत शिकायत आ रही है। इसके लिए हमें जागरूक होना है। संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वह आम जनमानस को जागरूक करें।

पुस्तक समीक्षा : अध्यात्म और यथार्थ का संगम है जलनाद का अंतर्नाद

(डॉ.दुर्गा सिन्हा ₹उदार₹-विनायक फीचर्स)

सागर की उत्ताल तरंगों से सुशोभित आकर्षक आवरण मुखपृष्ठ अंतर्मन के कोलाहल का आस्वाद करा रहा है। बहुत ही ख़ूबसूरत रंग संयोजन है। पुस्तक का आवरण पृष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,पाठकों को आकर्षित करने में। पढ़ने का मन सभी का हुआ होगा। जो भी देखेगा ज़रूर पढ़ेगा। बहुत-बहुत बधाई । शीर्षक भी स्वत: उद्घोष कर रहा है कि 'तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि मैं ही बनूँगा।'सारे वाद-विवाद , संवाद और नाद ,आज इसी के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। "जलनाद" इसी स्वर से न जाने कितने मधुर संगीत उपजे हैं। जल जीवन का पर्याय है।जल अमृत है। जल की आवाज़ मधुर व जीवनदायिनी है। सभ्यता-संस्कृति का विकास भी जल के किनारे ही हुआ। जल धारा जीवन का संकेत करती है। ऊपर से शांत अंदर कितना कोलाहल समेटे हुए है ,यह तो अन्तर्मन में झांक कर ही अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। सागर के उस शोर को किसने सुना, किसने जानना चाहा। आवरण पृष्ठ अपनी ओर आकर्षित कर यही संकेत कर रहा है कि मेरी अहमियत को जानो -पहचानो , समझो और स्वीकारो। वर्तमान की स्थिति तो और भी संकट भरी है। जलसंकट का संकेत जीवन को आगाह कर रहा है। सचेत कर रहा है। आज हम सभी को इस स्वर को सुनने की आवश्यकता है।प्रकृति के इस अनमोल ख़ज़ाने को अपने लिए ही सुरक्षित व संरक्षित करने की ज़रूरत है। गंगा प्रदूषित,पूजा कैसे करें ? नल है ,पर पानी रहित,शो की वस्तु ,कब तक सँभालें ? किस राज्य ने कितना पानी दिया और क्यों नहीं दे रहा ? सरकार और सत्ता खतरे में। कारण केवल जल। जल है तो जीवन है। जल बिना जीवन ही ख़तरे में आ गया है।

बारह खण्डों में पौराणिक, ऐतिहासिक,सामाजिक, सांस्कृतिक व सभ्यता विकास से प्रारम्भ होती जल की ध्वनि ,संकट की घड़ी का संकेत करती अपनी अहमियत दर्शाती, अपनी कोलाहल पूर्ण ध्वनि से आगाह कर रही है। शिकायत के साथ संरक्षण, संवर्धन और संचयन के लिए गुहार भी लगा रही है।

सागर मंथन की घटना और प्राप्त होने वाले रत्नों के साथ विष का उल्लेख,विषाक्त होता परिवेश, समाज और इंसान ,सभी का बहुत सटीक चित्रण। प्रारम्भिक जल गीत भी जल का संदेश बखूबी स्पष्ट कर रहा है। जल का होना न होना, कम या अधिक होना, सभी कुछ प्रभाव डालता है। अभाव या कमी ,जीवन संकट उत्पन्न करता है तो जल की अधिकता विनाश का कारण बनती है। अति वृष्टि -अल्प वृष्टि दोनों ही नुक़सानदेह है। प्रकृति के प्रतिकूल सारे कार्य प्रत्यक्षत:उपयोगी भले ही लें किन्तु जल देवता को नाख़ुश कर मानव जाति का भला हुआ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बाँध बना कर प्रवाह रोकना, नहर निकाल दिशा में परिवर्तन, जल से विद्युत उत्पादन , अंधाधुंध जल दोहन, मानव,विकास के नाम पर और स्वार्थ हित में न जाने कितने तरीके अपनाता रहा और अपना नुक़सान भी करता रहा, जो आने वाले दिनों में भयंकर परिणाम लाने की आगाही कर रहे हैं । पीने का शुद्ध जल बोतल में बंद होकर विषैला हो रहा है और जन मानस के लिए उपलब्धता में भी कमी आई है। जल स्तर दिनों दिन तेज़ी से गिरता जा रहा है। जल की शुद्धता जीवन के लिए ख़तरा बन गई है।

वर्तमान समय जल संरक्षण की माँग कर रहा है। इस दिशा में प्रत्येक व्यक्ति , समाज, राज्य और राष्ट्र को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी समस्या को ले कर विवेक जी ने नाटक के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रश्न सबके सामने रखने व समाधान की दिशा बताने का प्रयास किया है। कोई भी साहित्य दृश्य-श्रव्य और पठनीय तीनों ही माद्दा रखता हो तो समाज में उसकी क़ीमत बढ़ जाती है। वह स्वत: संग्रहणीय बन जाता है। केवल पढ़ कर मन पर जितना असर पड़ता है उससे कई गुना ज़्यादा नाटक के माध्यम से मंच पर देख व सुन कर पड़ता है। शब्द, वाक्य,परिस्थितियाँ,वस्तुस्थिति का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, यही कारण है कि नाटकों का प्रभाव तेज़ी से मन पर पड़ता है और दीर्घकालिक रहता है। अध्यात्म से जोड़ते हुए, रामचरितमानस में तुलसी दास जी द्वारा पंचतत्वों से रचित मानव शरीर में जल का महत्व बताते हुए,महाभारत काल की घटनाओं का समावेश ,साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं का समुचित उल्लेख कर सभी अंकों का चित्रांकन विलक्षण है। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम है यह नाटक। रिफ्रैक्शन , परावर्तन ,इंद्रधनुष के रंग , रंगों के चित्रण हेतु नृत्यात्मक प्रस्तुति की परिकल्पना सभी कुछ विवेक जी की विवेकशीलता का परिचय दे रहे हैं। जीवन के प्रारम्भ का अद्भुत दृश्य । कामायनी का प्रसंग , कथन को सार्थकता प्रदान कर रहा है। वर्तमान को वर्षों पूर्व के गहरे अतीत से जोड़ना अपने आप में एक विलक्षण दृष्टि का परिचायक है।

समुद्र मंथन की पौराणिक गाथा को वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आधार दे कर बड़ी ही कुशलता से प्रस्तुत किया है ताकि हर कोई इसे सहजता से स्वीकार कर ले। देवता-दानव , मोहिनी और विष्णु ,मानव के बाहर नहीं भीतर ही हैं। बहुत ख़ूब !

विवेक जी ने हर विषय पर अपनी पूरी पकड़ को सिद्ध कर दिया है। रोचक व ज्ञानवर्धक और संप्रेषण की सारी व्यवस्था ,विस्तार से बचा कर बहुत आसान बना दिया है नाटक को ,मंच पर प्रस्तुत करने के लिए। न तो अतीत के आस्था और विश्वास को मिटने दिया है न ही कपोल कल्पना कह कर नकारने का अवकाश दिया है , वरन् वैज्ञानिकता के आधार पर सिद्ध कर स्वीकार्य बना दिया है ताकि सब यथावत अस्तित्व में रहे। श्लाघनीय प्रयास। अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संयोग। कालिया नाग को नाथने का दृश्य जल प्रदूषण की विभीषिका का संकेत है। सँभलने की आवश्यकता है।

वाह ! नर्मदा व सोन नदी की पौराणिक गाथा को बड़ी ही वैज्ञानिकता से चित्रित किया है। वर्णन इतना प्रभावशाली है कि मंच पर दृश्य उभर कर सामने उपस्थित से जान पड़ते हैं। उद्गम अमरकंटक के बीहड़ों में। आज तो वहाँ भी वह नीरव प्राकृतिक सुन्दरता नहीं रह गई है। मनुष्य ने कृत्रिमता इतनी लाद दी है कि कुछ भी प्राकृतिक शेष नहीं रह गया है।

कंकरीट के जंगल वहाँ भी उगने लगे हैं। वहाँ की नीरव शांति और मधुर ध्वनि, जल का मीठा राग ,कानों में रस नहीं घोलते। यही विकास है शायद , कि सब अब बनावटी हो जाए और आत्मीयता समाप्त हो जाए।

वरुण देवता के विश्राम में विघ्न,असमय , कुसमय का विधान और न मानने से होने वाले नुक़सान का बड़ा ही तर्कसंगत वर्णन । रोचक घटना द्वारा महत्वपूर्ण संदेश । मंचन आसान नहीं। विवेक जी की परिकल्पना भले ही आसान है।

हालाँकि पौराणिक घटनाओं को परस्पर जोड़ने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक आधार अपने आप में विवेक जी की अद्भुत प्रतिभा की ओर इंगित करता है। "महाभारत का युद्ध जल के अपव्यय के तहत ही हुआ।"

न इस तरह की अनोखी रचना होती, न उपहास होता,न ही दुर्योधन अपमान का बदला लेता। बहुत ख़ूब !आज कृत्रिम झरने दिखावे के लिए जल का दुरुपयोग करते हैं और पानी बोतलों में बंद हो कर बिकने पर मजबूर है। संकट युद्ध की विभीषिका का आगाह कर रहा है।

कुम्भ मेले का आयोजन प्रायीनतम परम्परा का निर्वाह , आक्रांताओं ने भी बदलने का साहस नहीं किया।जल की सामाजिक महत्ता को ही प्रतिपादित करते हैं ये कुम्भ के मेले । धार्मिक पर्यटन , राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान और अनवरत चल रहे कुम्भ मेलों की प्रासंगिकता एवं अनिवार्यता पर प्रकाश डाला है कि कैसे ये मानसिक व शारीरिक शुचिता के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ प्रवचन, दीक्षा ग्रहण आयोजन आदि सम्पन्न होते हैं। आध्यात्मिक उन्नयन के आधार हैं ये सभी मेले और आध्यात्मिक टूरिज़्म के आयोजन ।

कालिदास के मेघदूत का उल्लेख, जल का मानवी करण,विलक्षण है। भारतीय परिकल्पना, कि "कण-कण में भगवान है।"जड़ भी चेतन है। पशु-पक्षी, नदियां,पत्थर भी पूजे जाते हैं। मेघों के द्वारा संदेसा भेजना, मेघों को संदेश वाहक बनाना , मेघों को सजीव समझना है। यही विशेषता है भारत की । विवेक जी ने घुनिंदा प्रसंगों के माध्यम से जल की महत्ता को शास्त्रीय नृत्य-संगीत द्वारा रोचक बना कर प्रस्तुत करने व संदेश देने का विलक्षण प्रयास किया है।

मांडू का जहाज़ महल ,वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की बचत संरक्षण व संवर्धन के उपायों के ऐतिहासिक प्रबंधन की ओर संकेत करता है। पानी का अभाव न था फिर भी दुरुपयोग न था। व्यर्थ पानी बर्बाद नहीं करते थे। क्या पूर्वज भविष्य दृष्टा थे ? शायद हाँ। तभी तो पुराने महलों व पुरानी इमारतों में घर में ये सारी व्यवस्थाएँ उपलब्ध थीं।

आज हम जानते-बूझते , देखते और महसूस करते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। कल कितना भयंकर होने वाला है अभी से पता चल रहा है। बोतलों में बंद महंगा पानी आगाह कर रहा है लेकिन हम फिर भी नहीं देखना चाहते ।

मांडू गई तो हूँ लेकिन तब जल संकट ऐसा न था कि महल को इस दृष्टि से भी देखने का प्रयास किया जाता । आज हर किसी को इस नज़रिए से देखना और अमल में लाने का विचार करना ज़रूरी बन गया है। इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र अध्यात्म और विज्ञान का अनूठा संगम है " जलनाद " ।विवेक जी की परिकल्पना अद्भुत है और प्रस्तुति का स्वरूप अद्वितीय - अप्रतिम ।

नदी की मनोव्यथा

नदी चीख़ कर कहती है मेरी दुर्दशा के ज़िम्मेदार मानव तुम ही हो और अब तुम ही मेरा उद्धार करोगे । नदियों ने हमें जल दिया,जीवन दिया, सभ्यता दी, संस्कृति दी, प्राण भरे,अब हमारी बारी है समझने की । अपने उत्तरदायित्व को समझें और निर्वाह करें। नदी स्वयं अपनी व्यथा - कथा , क्षति ,असमर्थता का प्रलाप कर रही है और अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगा रही है ,चेतावनी देते हुए। 'सौ साल पहले हमें जल से प्यार था।' जी हाँ हम खेल भी यही खेलते थे और गीत भी यही गाते थे ।"गोल-गोल रानी इत्ता-इत्ता पानी " और " मछली जल की रानी है ।" शायद यह भविष्य का संकेत था कि जब जल कम रह जाएगा या सिर से ऊपर हो जाएगा तो जीवन नहीं बच पाएगा।

गंगा जल और आब-ए-ज़मज़म और बयतिस्मा की ख़ासियत भी विवेक जी ने बख़ूबी याद रखे है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी का गहराई से अध्ययन कर ,नाटक को सशक्त बनाने के लिए आवश्यकतानुसार बख़ूबी उपयोग किया है विवेक जी ने। जल मानव जीवन की औषधि है । प्राणी जगत के जीवन का आधार है तो हर धर्म में इसकी अहमियत और पवित्रता की चर्चा समान रूप से होनी ही है। धार्मिक आधार पर मौलवियों -पंडितों , गुरुजनों के माध्यम से सारगर्भित जानकारी देते हुए जल संचयन की ताकीद करता " जलनाद " नाटक, ।

जल तरंग ,जल वाद्य यंत्र जिसमें निर्धारित आकार के बर्तनों में निश्चित मात्रा में जल भर कर मधुर ध्वनि प्राप्त की जाती है। जल तरंग मात्र एक विशिष्ट वाद्य यंत्र नहीं,पंचतत्वों का संगम है। जिसमें जल तो है ही,कठोरी - भूमि,जल का तापमान अग्नि,वातावरण यानि आकाश और वायु ।पाँचों तत्व मिल कर निर्मित है। ऋग्वेद की ऋचाओं द्वारा व उनके भावार्थ को गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर नाटक को एक महान ग्रंथ के रूप में ला खड़ा किया है,

विवेक जी ने । इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई ।

वस्तुत: यह महज़ एक नाटक नहीं विलक्षण ग्रंथ है, पठनीय, संग्रहणीय और मंचनीय।

हे जल के देवता !

यही ख़ासियत है भारत की कि,जल भी देवता है। जिससे हमें जीवन मिले वह देवतुल्य हो जाता है। ऋग्वेद की ऋचाओं का लक्ष्यभेदी हिन्दी रूपांतरण भी प्रभावशाली है। विवेक जी के ज्ञान-विज्ञान और अध्यात्म के मिश्रण को नमन जल रसायन की विस्तृत समीक्षा, व्याख्या एवं स्वरूप का आद्योपांत रोचक वर्णन सराहनीय। भाषा-शैली, सुरुचि पूर्ण एवं कथ्यानुरूप। विवेक जी की इस विलक्षण कृति की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कम से कम मैंने तो यही अनुभव किया है। स्त्री-पुरुष स्वर में सूत्रधार की भूमिका नाटक में जान डाल रही है। बहुत ही सलीके से सभी परिस्थितियों को उजागर करते हुए नाटक के प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता जगाती जानकारी दर्शक को बांधे रखने में पूर्णत: समर्थ है। एक अलग ही अनोखापन है। विवेक जी की परिकल्पना को बारम्बार बधाई । मुझे यह नाटक ख़ास पसंद क्यों आया या मैं विशेष रूप से इधर आकर्षित क्यों हुई , कारण यह है कि मैंने भी एक नाटक संग्रह "कौन सीखे-कौन सिखाए "प्रकाशित किया है,जिसमें चुने हुए नाटक , राज्य स्तर पर पुरस्कृत एवं दूरदर्शन व आकाशवाणी से प्रसारित हैं। मैंने भी संसाधन संरक्षण, आपदा प्रबंधन, साम्प्रदायिकता के कुप्रभाव से ख़ुद को परे रखने एवं साक्षरता के महत्व से लगते नाटकों की रचना की, जिनकी मंचीय प्रस्तुति पाठकों व दर्शकों को बहुत पसंद आयी। ख़ूब सराहना मिली। विवेक जी का यह नाटक अद्भुत है। सत्य-तथ्य, गल्प और पौराणिकता की वैज्ञानिक आधारशिला से समृद्ध ,भारतीय सभ्यता-संस्कृति ,आस्था व विश्वास को ठोस बनाती यह कृति न केवल पठनीय है वरन्मैं तो कहती हूँ कि संग्रहणीय है। सभी बुद्धिजीवियों की लाइब्रेरी में होनी ही चाहिए।साथ ही इसका जितना अधिक से अधिक मंचन किया जा सके उतना श्रेयस्कर है।

विवेक जी के सूक्ष्म अवलोकन , समसामयिक समस्या के प्रति चिंतित होना,बख़ूबी अभिव्यक्त हो रहा है। शब्द चयन,संवाद,भाषा-शैली एवं सम्प्रेषण कला का,परिचय मिल रहा है। प्रस्तुति रोचक और प्रभावशाली है। नाटक मंचन की पूरी-पूरी व्यवस्था भी कर रखी है विवेक जी ने कि कोई दिक़्क़त न हो। सूक्ष्मतम जानकारी पूरे विस्तार से दी गई है ,जो अपने आप में विलक्षण है। बहुत-बहुत बधाई एवं आकाश भर हार्दिक शुभकामनाएं * ।(विनायक फीचर्स)(लेखिका काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व व्याख्याता हैं एवं वर्तमान में अमेरिका में निवासरत हैं।)*

आई ए एस पूजा सिंघल को 28 महिनों बाद जमानत

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड, झारखंड

रांची, मनी लांड्रिंग से मनरेगा तक की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा की महिला अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महिनों के बाद आज बी एन एस की नई धारा 479 के तहत जमानत मिली है । जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तब मनरेगा का बड़ा घोटाला हुआ था। जिसके कारण 6 मई 2022 उनके आवास पर छापा मारा गया तथा 11मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया गया था। निलंबन के समय पूजा के पास खान तथा उद्योग दो विभाग थे।वह खनन विभाग की सचिव भी रही । रघुवर सरकार वह कृषि सचिव भी थी ।

खनन क्षेत्र में राजस्व का स्रोत अध्ययन के लिए झारखंड की टीम ओडिशा जायेगी

खनन से ओडिशा कमाता 40,000करोड, झारखंड महज 12000 !!

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

सरायकेला, खनीज संपदा से भरपूर झारखंड, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ की भूमि जो सरकार को अपनी सीने से राज्य की तिजोरियां भरते वही अब झारखंड सरकार की एक टीम ओडिशा सरकार की श्रोत को जानेगी । यह बात झारखंड में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक में ही अतिरिक्त राजस्व संग्रहण के नए स्रोत तलाशने का निर्देश दिने के बाद यह निर्णय लिया गया है । इसे लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि वह खनन क्षेत्र से राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम ओडिशा भेजेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड के पास देश के खनिज भंडार का 40 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बावजूद राज्य खनन क्षेत्र से सालाना केवल 11-12 हजार करोड़ रुपये कमाता है, जबकि पड़ोसी ओडिशा लगभग 40,000 करोड़ रुपये कमाता है। किशोर ने शनिवार को समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, 'हमें राज्य का राजस्व बढ़ाने के तरीके तलाशने की जरूरत है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095 . newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023